www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 40 गोरखपुर, 20 अप्रैल 2025 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

देश की संप्रभुता को प्रभावित करती मालदा और मुर्शिदाबाद की सांप्रदायिक आग

पूर्व में असम के दंगे के विरोध में मुंबई के आजाद मैदान में मुस्लिम अराजकतावादियों किस तरह धरना प्रदर्शन कर कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थीं और अमर ज्योति को नुकसान पहुंचाया गया था। तब देवबंद दारुल उलूम के मुट्ठी भर मौलानाओं की धमकी से डर कर राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में सलमान रुश्दी को नहीं आने दिया था। ममता सरकार ही नहीं देश के उन सभी तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक दलों को समझना होगा। तुष्टीकरण की राह पर चल कर वह वोट बैंक को साध सकते हैं लेकिन यह प्रवृत्ति देश की संप्रभुता के लिए घातक और विध्वंसक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले हर उपद्रव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी भूमिका होती है। मुर्शिदाबाद में भी उनकी भूमिका से इनकार नही किया जा सकता है। यह देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। यदि ममता सरकार तुष्टीकरण की ही माला जपती रही तो वह दिन दूर नहीं जब मुर्शिदाबाद और मालदा से उठने वाली साम्प्रदायिक आग की लपटें देश को झुलसा देंगी।

मीडिया का एक बड़ा विभाग जो हिन्दू संघटनों को लेकर आये दिन आग उगलता रहता है वह भी मौन धारण किए हुए है। गौर किया जाये तो सेक्युलर दलों और मीडिया की यह चुप्पी कोई नई नहीं है। स्मरणीय है कि देश को सत्तारुढ़ संप्रग सरकार के दौरान हुर्रियत के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अपने आग लगाऊ मित्रों को भीड़ जुटा कर कश्मीर की आजादी की मांग करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश और संविधान की संप्रभुता के खिलाफ वाक् जुगाली की तब देश की संप्रग सरकार, मीडिया का एक वर्ग और सेक्युलर राजनीतिक दल अपनी जबान बंद किए रहे। गतवर्ष डेनमार्क में पैगंबर के कार्टून को लेकर जब भारतीय मुसलमानों ने जमकर उत्पात किया तब भी यह जमात खामोश था। देश समझ नहीं पाता है कि दूसरे देश में घटित घटनाओं की आड़ लेकर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है? जब कि यह तथ्य है कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में प्रतिदिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कहर बरपा रहा है। आज उनकी जनसंख्या घट कर विनाश के कगार पर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम कट्टर पंथी सड़कों पर उतर कर अराजकता फैलाने, पुलिस पर हमला बोलने घरों में आग लगाने, हिन्दू अल्प संख्यकों की संपत्ति लूटने और घर में घुसकर उन्हें मारने, अपमानित करने पर ममता बनर्जी जिस प्रकार से आंखें बंद किए रहीं उससे देश की संप्रभुता लहूलुहान हुई है। मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा, दक्षिण चौबीस परगना और हुगली जिले में भी जमकर आगजनी और उत्पात हुआ है। इन सबके बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने इस अराजकता को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इस अराजकता पर हम आंखें बंद नहीं रख सकते। उसने मुर्शिदाबाद जिले में केन्द्रीय पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया है। यादि अदालत ने सख्त रुख नहीं दिखाया होता तो ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी होती ममता सरकार। देश की मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस तरह के हिंसक प्रदर्शन से मुस्लिम समाज का भला हो सकता है किया अपनी अभिव्यक्ति और विरोध को जताने के लिए लोकतान्त्रिक तरीका नहीं आजमाया जा सकता। आखिर हिंसा देगा और कटुता का भाव समाज के लिए किस तरह हितकर साबित हो सकता है। गौर किया जाए तो यह पहली बार नहीं है जब विरोध के नाम पर कट्टरपंथी तत्वों द्वारा सड़कों पर उतर कर हिंसा का नंगा नाच किया गया हो। स्मरणीय है कि गत वर्ष पहले मालदा के कालिया तक में मुस्लिम समुदाय के कट्टर पंथी तत्वों ने अराजकता का प्रदर्शन कर अपनी ताकत का अहसास कराया था सांप्रदायिक नारे लगाते हुए पुलिस के हथियारों को लूटा गया और महिला कांस्टेबलों के साथ छेड़-छाड़ की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कठोर कदम उठाए गए लेकिन विचलित करने वाला तथ्य यह कि ममता सरकार अपने उत्तरदायित्व से विमुख है और उपद्रवियों का हौसला बुलंद है। हिंसा के दौरान जिस तरह सरकार और तंत्र हाथ पैर हाथ धरे बैठा रहा, माता तमाशा बिन रहा, और वक्फ कानून की खिलाफत करने वाले सड़कों पर उतरकर उपद्रव करते रहे उससे साफ है कि भीड़ को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। निः संदेह भीड़ को अपनी बात कहने और विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन यह कहां तक उचित है कि लोकतांत्रिक विरोध की आड़ में अराजकता का प्रदर्शन किया जाए। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वह देश के लिए अपशगुन है। आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इससे राष्ट्र की संप्रभुता लहूलुहान हुई है। समुदायों के बीच नफरत पनपी है जिस तरह उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन मीडिया और आमजन को निशाना बनाया है। उससे साफ इंगित होता है कि उनका मकसद अपनी बात कहना नहीं बल्कि अपने उग्र सांप्रदायिक आचरण से सामाजिक वातावरण को विषाक्त बनाना था। ध्यातव्य है कि वे इसमें कामयाब रहे। मुर्शिदाबाद की घटना से सरकार घेरे में फंस गई। ममता सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में उचित है कि केंद्र की सरकार इसे गंभीरता से ले और ममता सरकार से सवाल करे। देश भी जानना चाहेगा कि क्या ममता सरकार ऐसे समाज विरोधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? इसको उम्मीद कम ही है। कारण, ममता सरकार को तुष्टीकरण पसंद है। वह खुले आम अल्पसंख्यक वोट बैंक को राजनीति करती है।

वास्तविकता यह कि तुष्टीकरण के मामले में वह पूर्ववर्ती सरकार को पीछे छोड़ दी है। राज्य में कट्टर किस तरह हावी हो चुका है। वह इसी से समझा जा सकता है कि -अभी गत वर्ष पहले एक मदरसा शिक्षक काली मासूम अख्तर को सिर्फ इसलिए निशाने पर लिया गया कि राष्ट्रगान जन गण मन के गायन की वकालत की थी लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें न सिर्फ मदरसे से निष्कासित किया गया बल्कि उसकी पिटाई भी की गई।

बच्चों की चोरी पर सख्त रोक

सर्वोच्च न्यायालय का अस्पतालों से नवजात की चोरी और बाल तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने लिए अस्पतालों का लाइसेंस निलम्बित करने का निर्देश जनहित में बड़ा फैसला है। इस सम्बन्ध में शीर्ष न्यायालय का यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि किसी भी अस्पताल से यदि कोई भी बचा चोरी होता है तो सबसे पहले उस अस्पतालका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। अस्पताल में बच्चे की हर तरह से सुरक्षा और संरक्षण अस्पताल की महती जिम्मेदारी है। इसमें किसी तरहकी लापरवाही अक्षम्य है। साथ ही निचली अदालतों को बाल तस्करी के मामलों की रोजाना सुनवाई कर छह महीने में निबटारा करने का निर्देश भी उचित और त्वरित न्यायकी दिशा में अच्छी पहल है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने गत मंगलवार को देशभर के उच्च न्यायालयों को भी निर्देश दिए हैं कि ट्रायल कोर्ट में बाल तस्करी के लम्बित मामलों की स्थिति का पता करें और उन्हें छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी करें पीठ का यह कहना अदालतों को कड़ा सन्देश है कि निदेशों के अमल में किसी तरह की ढिलाई शीर्ष कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। शीर्ष कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं आसपास के अस्पतालों में बच्चा चोरी की घटनाओं के संदर्भ में की, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालयने 2024 में बाल तस्करी के आरोपियों के एक समूहको जमानत दे दी थी और इसी के साथ आरोपितों को जमानत का उच्च न्यायालय का आदेश रद कर दिया। ऐसे मामलों एवं अपराध की गम्भीर प्रकृति और आरोपियों की कार्य-प्रणाली की अन्देखी कर अपने विवेक से आरोपियों के पक्ष में फैसला देना कानून की शुचिता पर सवाल खड़ा करता है। इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ता हैं और उन्हें फरार होने का मौका मिलता है। ज्योतिष और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभिभावकों को भी बच्चों के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

कांग्रेस और विपक्षी दलों को हमेशा यही डर सताता रहा कि...

कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश के मुस्लिम समुदाय को अछूत जैसा बना दिया है। अर्थात उनके मामले में कानून और अदालत कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसा करना मुसलमानों के आंतरिक मामलों में दखल देना है। ऐसा करने से मुसलमानों के धर्म पर भी असर पड़ सकता है। ऐसी धारणा ने जन्म लिया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण। कांग्रेस और विपक्षी दलों को हमेशा यही डर सताता आ रहा है कि किसी तरह के कानून में परिवर्तन करने से कहीं देश के मुस्लिम मतदाता नाराज न हो जायें। वोट बैंक के फिसलने के डर से मुसलमानों को डराये रखा गया। भले ही ऐसे बदलावों का फायदा मुस्लिम समुदाय को ही क्यों न हो। इसके बावजूद विपक्षी दल किसी भी तरह के संशोधन के खिलाफ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों के खैरख्वाह बनने वाले राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहने के दौरान मुसलमानों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हो। विपक्षी दलों को मुस्लिम वोटों के डर का सबसे बड़ा उदाहरण- शाह बानों का प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के एवज में मुआवजा देने के निर्माण के बावजूद केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद में इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया इससे ही साफ हो गया था कि देश की मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक का दर्द झेलने के बाद अपने गुजारे भत्ते के लिए धक्के खाएं किंतु उन्हें कानून के तहत न्याय नहीं मिल सकता।

हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई अब आर-पार की स्थिति में पहुंची

केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई अब आर-पार की स्थिति में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में गत बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और दो जजों की खंडपीठ मे शुरू हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल में जिस तरह के प्रावधान किए हैं उससे स्पष्ट हो गया है, केंद्र सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। उनकी दान की हुई संपत्ति पर सरकार हक जताना चाहती है। वक्फ संपत्ति पर सरकार अपने हिसाब से नियंत्रण करना चाहती है। मुसलमानो के धार्मिक क्रिया-कलापों पर शासन हस्तक्षेप कर मुसलमानो पर अंकुश लगाना चाहती है। यह संशोधन से स्पष्ट है। इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देशभर के मुसलमानों के साथ-साथ अन्य अल्पसंख्यक सामुदायों में भी हो रही है। पिछले 11 वर्षों से मुसलमानो के साथ में जो भेदभाव केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, वक्फ अधिनियम के रूप में वह सामने आ गया है। अभी तक मुसलमान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वह किसी भी किस्म का विरोध नहीं कर रहे थे। इस अधिनियम ने उन सब को एकजुट करके लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति की जा रही है। क्या ऐसी ही

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कसौटी पर कसा जाना है। संविधान में बिना संशोधन किए हुए जिस तरह से वक्फ बिल के द्वारा करोड़ों मुसलमानो के धार्मिक क्रियाकलाप और इबादत करने को लेकर सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है।

नियुक्ति अन्य गैर मुस्लिम बोर्ड में की जा सकती है। हिंदू मंदिरों और हिंदू बोर्ड में गैर हिंदुओं की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किये। 13 वीं, 14वीं शताब्दी और सैकड़ो वर्ष पुरानी मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किये। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए। संविधान में अल्पसंख्यकों को तथा सभी नागरिकों को अपने धर्म को पालन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अधिकार भी इस संसोधन में बाधित हो रहे हैं। पांच साल का प्रैक्टिशनर मुसलमान ही वक्फ मे दान कर सकता है। इस तरह के सवालों का जवाब सालिस्टर जनरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका के ऊपर यह आरोप लगते रहे हैं, वह सरकार के दबाव पर काम करती है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कसौटी पर कसा जाना है। संविधान में बिना संशोधन किए हुए जिस तरह से वक्फ बिल के द्वारा करोड़ों मुसलमानो के धार्मिक क्रियाकलाप और इबादत करने को लेकर सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है। यह महत्वपूर्ण हो गया है। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने में आनाकानी करती है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ में असंवैधानिक कार्यों को न्यायपालिका संरक्षित और बढ़ावा देने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस बार विपक्ष के राजनीतिक दलों, 6 राज्य सरकारों तथा मुस्लिम संगठनों के साथ ही साथ अन्य समुदाय के लोगों व संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारत में हिंदू- मुसलमानो के बीच आर-पार की लड़ाई के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय मुसलमानो को संविधान पर भरोसा था। धार्मिक स्वतंत्रता थी। जिस तरह का हस्तक्षेप कानून की आड़ में किया जा रहा है इसे कोई जिंदा कौम स्वीकार नहीं कर सकती है। भारत में अभी मुस्लिम भेड़ की तरह नहीं हांके जा सकते हैं। इतना तय है। सरकार विपक्षी दलों को भी इसी तरीके से दबाने का काम कर रही है। इस मामले में अब विपक्षी दल भी खुलकर सामने आ गए हैं। वह भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुसार न्याय देने में सक्षम हुई तो इससे न्यायपालिका के प्रति जो लोगों में अविश्वास बढ़ रहा था, वह अविश्वास खत्म होगा। न्यायपालिका और संविधान के प्रति एक बार फिर सभी का विश्वास जागृत होगा। ऐसी आशा सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है।

नए वक्फ कानून को लेकर सांप्रदायिक होता हिंसा का सिलसिला

बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा का सिलसिला जिस तरह तेज और सांप्रदायिक होता जा रहा है, जिस तरह से हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मुर्शिदाबाद से पलायन को विवश किया जा रहा है, वह मुस्लिम तुष्टीकरण और दुष्प्रचार की खतरनाक राजनीति का प्रतिफल तो है ही, वह कुशासन एवं अराजकता की भी चरम पराकाष्ठा भी है। नए वक्फ कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को विशेषतः किशोर बच्चों को हिंसा एवं तोड़फोड के लिये जानबूझकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं। वे उन्हें अराजकता एवं उन्माद के लिए उकसा भी रहे हैं और तरह-तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं।

अराजकता फैलाने वाले किस तरह बेखौफ हैं, इसकी पुष्टि इससे होती है कि वे सरकारी-गैरसरकारी वाहनों को तोड़ने, जलाने के साथ पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। बंगाल के विभिन्न जिलों में वक्फ कानून के विरोध के बहाने फैलाई जा रही अराजकता इसलिए भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ खड़ी होकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का बढ़ना, हिन्दुओं में डर पैदा होना, भय का वातावरण बनना, आम जनजीवन का अनहोनी होने की आशंकाओं से घिरा होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है।

यह बंगाल पुलिस के नाकारापन एवं ममता सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण का ही दुष्परिणाम है कि मुर्शिदाबाद के साथ ही अन्य शहरों में भी वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हिंसा, तोड़फोड, आगजनी हो रही है। खतरनाक यह है कि इस दौरान हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वक्फ कानून विरोधियों की अराजकता से उपजे हालात का संज्ञान लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इससे शर्मनाक एवं दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। उनके पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया है।

इस हिंसा की जांच एजेंसियों ने पोल खोल दी है, यह हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें तुर्की से फंडिंग और स्थानीय मदरसों की मिलीभगत सामने आई है। हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई और इनाम की व्यवस्था भी की गई थी। ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी एवं नेता बन गई है जिसका देश के संविधान, न्यायपालिका एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया है। वक्फ कानून का विरोध करने सड़क पर उतरे तत्वों के दुस्साहस का पता इससे चलता है कि वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। उनके इसी दुस्साहस के चलते मुर्शिदाबाद के हिंदुओं ने खुद को असहाय पाया। बंगाल में कानून के शासन ने सुनियोजित हिंसा के दुष्चक्र के समक्ष एक बार फिर समर्पण कर दिया। बंगाल में इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। मई 2021 में विधानसभा चुनावों के बाद वहां तृणमूल समर्थक तत्वों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को इतना आतंकित किया था कि वे जान बचाने के लिए असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। तब भी वहां पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। ताजा हिंसक हालातों में राज्य सरकार और उसके नेता यह झूठ देश के गले में उतारने में लगे हुए हैं कि बंगाल में स्थितियां नियंत्रण में हैं। यह कैसा नियंत्रण है? यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा दोगलापन है? जिसमें एक समुदाय खुलेआम दूसरे समुदाय को निशाना बना रहा है। खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्र-विरोधी विचारों का जहर घोला जा रहा है।

वक्फ कानून में संशोधन का विरोध विडम्बनापूर्ण होने के साथ देश में अराजकता फैलाने का माध्यम बना हुआ है। वक्फ कानून में संशोधन के तहत किसी

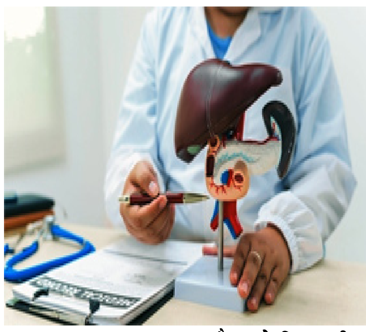


मस्जिद, मदरसे आदि को लेकर किसी भी तरह के नुकसान, कब्जा करने या दखल की बात नहीं कही गयी है। इसके विरोधी चाहे जो तर्क दें, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए थे और सरकारी-निजी जमीनों पर मनमाने तरीके से दावा कर दिया करते थे। उनकी इस मनमानी का शिकार अनेक मुस्लिम भी थे। क्या वक्फ कानून के विरोधी यह बताने की स्थिति में हैं कि वक्फ बोर्डों ने अभी तक कितने गरीब मुसलमानों की सहायता की? यह पहली बार नहीं है, जब किसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उपद्रव, हिंसा, आगजनी की जा रही हो। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया था। तब यह झूठ फैलाया जा रहा था कि इस कानून के जरिये मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब यह झूठ फैलाया जा रहा है कि नए वक्फ कानून के जरिये सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। यह निरा झूठ और शरारत ही है। वक्फ कानून के विरोधी भले ही लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हों, लेकिन ये उसकी धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। वे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं।

मुर्शिदाबाद हिंसा के जरिए पूरे बंगाल में हिंसा फैलाने का प्लान तुर्की में बनाया गया था, इसके जरिए बंगाल के हालात भी ठीक बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश थी। हिंसा को लेकर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई थी कि कौन कहां नुकसान करेगा और लूटपाट मचाएगा। इसके साथ ही इनाम देने को लेकर योजनाएं बनाई गयी। हिंसा के दौरान इस बात का खास ध्यान देने का अलर्ट किया गया कि रेल और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट न चल पाए। मौका मिलने पर हिंदुओं की हत्या करना भी टारगेट था। कुछ हिन्दुओं को मारा भी गया है। हिंदुओं के घरों के साथ मंदिरों पर हमले किए गए, घर जलाए गए, आजीविका नष्ट की गई, बलात्कार की धमकियां दी गयी, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले न केवल सांप्रदायिक घृणा में डूबे हैं, अराजकता एवं उन्माद पर सवार है, आतंकी माहौल बनाकर हिन्दुओं को भयभीय-आतंकित करना चाहते है। क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली। ज्यादा चिन्ताजनक तो यह है कि अराजक लोग चाहते हैं पलायन करने के लिए मजबूर लोग फिर कभी अपने घरों को न लौट पाएं। इन जटिल एवं अनियंत्रित होते अराजक हालातों में शांति, सौहार्द एवं सामान्य हालातों को निर्मित करने के लिये आवश्यक है कि केंद्र सरकार बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए, बल्कि यह भी अपेक्षित है कि सुप्रीम कोर्ट वहां के हालात का स्वतः संज्ञान ले। उसे वक्फ कानून विरोधी हिंसक तत्वों के उपद्रव के लिए ममता सरकार को जवाबदेह बनाना ही होगा।

ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। ममता अपने बलबूते चुनाव जीतने का माद्दा रखती है तो फिर हिंसा का सहारा क्यों लेती है? अराजकता फैलाकर अपने ही शासन को क्यों दागदार बनाती है? क्यों अपने प्रांत की जनता को डराती है, भयभीत करती है? क्या ये प्रश्न ममता की राजनीतिक छवि पर दाग नहीं है? ममता एवं तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। ताजा हिंसक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक, गैर-कानूनी एवं राष्ट्र-विरोधी कार्यों को अंजाम दिया है। बंगाल में तो भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, हिंसा की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगल रहा है। ममता अपनी जातियों, ग्रुपों और वोट बैंक को मजबूत कर रही हैंझ देश को नहीं।

स्वस्थ लीवर के लिए सही आहार का पालन करना महत्वपूर्ण



जयपुर। हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम भोजन ही दवा है- है, जिसका अर्थ है कि स्वस्थ लीवर के लिए सही आहार का पालन करना महत्वपूर्ण है।

विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जो हर साल लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लीवर से जुड़ी बीमारियों और उनके उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करना है। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि खून को साफ करना, पोषक तत्वों को संसाधित करना और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना।

ब्रिटिश लीवर ट्रस्ट के अनुसार, विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम भोजन ही दवा है है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि स्वस्थ भोजन लीवर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

लिवर डे मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को लीवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे लीवर से जुड़ी बीमारियों से बच सकें और अपने लीवर को स्वस्थ रख सके।

स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में युवाओं का किताबों के प्रति बढ़ रहा रुझान

पुस्तकें हमारे मार्गदर्शक, एक मित्र, एक गुरु के रूप में हमें ज्ञान प्रदान करती हैं एवं हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सदियों से पुस्तकें ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत रही हैं। एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां भारत की ज्ञान-परंपरा को बहुत ही सुदृढ़ रूप में हमें अपने स्वर्णिम काल से जोड़ती हैं। ये पांडुलिपियां सिर्फ हमारे धर्म और संस्कारों के विषय में ही नहीं, अपितु गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोलविज्ञान और वास्तुशास्त्र के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं और हमें उस समय की ज्ञान-परंपराओं, संस्कारों, कला एवं संस्कृति की भी सही जानकारी प्रदान करती हैं।

सोचिए, अगर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखी होती और उसे पढ़कर तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस की रचना नहीं की होती तो क्या हम मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम को जान पाते। क्या रामायण के विभिन्न भाषाओं में करीब 331 संस्करण तैयार हो पाते। आज पुस्तकें मुद्रित एवं ई-पुस्तक दोनों रूपों में उपलब्ध हैं। विभिन्न व्यक्तियों के ब्लाग, यूट्यूब चैनल तथा अन्य इंटरनेट माध्यमों से भी ज्ञान मिलता है, लेकिन मुद्रित पुस्तकों का अपना अलग ही महत्व है।

एक समय था जब पाठकों को पुस्तकालयों की अत्यंत आवश्यकता थी, मगर अब पुस्तकालयों के साथ-साथ पाठकों के पास ज्ञान के और भी स्त्रोत हैं, लेकिन पुस्तकों का महत्व भूतकाल में भी था, वर्तमानकाल में भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। उनका रूप बदल सकता है, वो आडियो या ईबुक के रूप में हो सकती हैं।

सूचना वैज्ञानिक एफ. डब्ल्यू. लैनचेस्टर ने 1980 में एक भविष्यवाणी की थी कि 20वीं शताब्दी के अंत तक पूरी तरह से हम कागज रहित हो जाएंगे, लेकिन तब से लेकर अब तक भी कागज का उपयोग बढ़ा है, घटा नहीं है। ये बात सही है कि हम डिजिटल युग की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, किंतु मुद्रित पुस्तकों का उपयोग आज भी महत्वपूर्ण है। विषय सामग्री चाहे ईबुक के रूप में ही क्यों न हो, लेकिन आज भी ज्यादातर व्यक्ति उसका प्रिंट निकालकर पढ़ना ही पसंद करते हैं।

भीड़ बता रही भविष्य

एक विचार जो सभी के मस्तिष्क में बैठ गया है कि सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसे हमें बदलना होगा। यह सत्य है कि इंटरनेट पर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी है। साथ ही साथ इंटरनेट पर मिथ्या, अप्रमाणित, पक्षपाती एवं गलत ज्ञान का भी भंडार है। इस तरह के ज्ञान के उपयोग से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी शिक्षा एवं अनुसंधान गलत दिशा में जा सकता है। विश्व पुस्तक मेला जो हर वर्ष प्रगति मैदान (भारत मंडपम) में आयोजित किया जाता है, यहां अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों तथा पुस्तकप्रेमियों की संख्या में युवाओं की भीड़ उम्मीद दशार्ती है कि मुद्रित पुस्तकों के प्रति रुझान कम नहीं हुआ है।



सही मायने में पुस्तकें समाज का दर्पण होती हैं। यदि हमें किसी देश के समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति तथा अन्य किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो पुस्तकों से महत्वपूर्ण कोई भी स्त्रोत नहीं हो सकता। एक पुस्तक लिखने के लिए लेखक बहुत सारे संदर्भों का अध्ययन करता है और उन संदर्भों अर्थात पुस्तकों, पत्रिकाओं इत्यादि को पढ़कर उनमें उपलब्ध ज्ञान को संग्रहीत कर नूतन ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में इस ज्ञान का देश के लिए, समाज तथा विश्व के लिए क्या महत्व है, ये सब ज्ञान हमें पुस्तकें ही प्रदान करती हैं।

बदलना होगा पढ़ाने का तरीका

यूं तो हम ईबुक में गुम नई पीढ़ी पर दोषारोपण करते हैं कि वो किताबों के प्रति उनसे पहले की पीढ़ी से अधिक उदासीन हैं, किंतु इसके लिए कहीं-ना-कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था एवं अध्यापक भी जिम्मेदार हैं। हमारे अध्यापक उतना समय नहीं देते, जितना उनको देना चाहिए। उनको शिक्षा प्रणाली में केस आधारित, स्टोरी टेलिंग तथा प्रोजेक्ट आधारित इत्यादि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि दादा-दादी, नाना-नानी की कहानियां, जो उन्होंने हमें बचपन में सुनाई थीं वे आज भी हमें याद हैं। हमें अपनी पूरी शिक्षा-प्रणाली को रोचक बनाना होगा चाहे कथा सुनाना हो, पुस्तक प्रतियोगिता या क्विज कांटेस्ट के माध्यम से, किसी-ना-किसी रूप में युवाओं को पुस्तकों से जोड़ना होगा। पुस्तकों के विषय में युवाओं में उत्सुकता पैदा करनी होगी। अध्ययन की आदतों को बढ़ाना होगा।

ऐसे सुधरेगी स्थिति

गत वर्षों में भारत सरकार की संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित क्षेत्रीय पुस्तक मेले तथा साहित्यिक मेलों में कुछ उत्साहवर्धक वृद्धि देखने को मिली है। यह एक शुभ संकेत है। इस दिशा में नई शिक्षा प्रणाली 2020 में कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनकी सार्थकता को सारगर्भित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा कि पुस्तकालयों की स्थिति को अच्छा बनाएं। प्रौद्योगिकी और कुछ रणनीतियों का लाभ उठाकर, हम युवाओं में पठन-पाठन की प्रक्रिया एवं पढ़ने की रुचि को और तेज कर सकते हैं। इसके लिए निश्शुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करा रहीं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आफ इंडिया तथा अन्य डिजिटल रिपाजिटरी, अभिलेखागार प्रोजेक्ट, गुटेनबर्ग जैसे प्लेटफार्म को प्रोत्साहित करना होगा।

स्कूलों और कालेजों में बुक क्लब, कहानी सुनाने के सत्र और वाद विवाद एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए गेमिफिकेशन तकनीकों, जैसे कि रिवार्ड आधारित रीडिंग ऐप का उपयोग करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर लघु रूप पुस्तक समीक्षा और चर्चा को बढ़ावा दे सकते हैं। स्कूलों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक स्थानों पर आरामदायक बैठने की जगह और विविध पुस्तकों को पढ़ने के लिए अच्छे आधुनिक पुस्तकालयों को स्थापित करना होगा। पुस्तकों के अध्ययन में रुचि बढ़ाने के लिए एक प्रयास परिवार की तरफ से भी करना होगा, क्योंकि बच्चें जो देखते हैं, वही सीखते हैं।

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे मदरसे के बच्चे



निचलौल। ब्लॉक क्षेत्र के सोहगीबरवा में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीण तीसरे दिन बृहस्पतिवार को भी धरना-प्रदर्शन पर बैठे है। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों के समर्थन में मदरसे के बच्चे भी उतर गए। ग्रामीणों की मांग पूरा करने के लिए बच्चे भी पूरे दिन धरना-प्रदर्शन पर बैठे रहे। हालांकि तीसरे दिन धरना स्थल पर किसी भी विभाग के जिम्मेदार नहीं पहुंचे। जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ते देखा गया।

सोहगीबरवा गांव के बाजार स्थित एक भवन पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे लोरिक सहानी, सुदामा कुशवाहा, बिहारी जायसवाल, साकिर, भूपेंद्र यादव, श्रवण भगत, डॉ. सुभाष यादव, गोपाल आदि ने कहा कि निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के गांव सोहगीबरवा, शिकारपुर और भोतहा नारायणी नदी और घने जंगलों के बीच घिरा हुआ है। इतना ही नहीं यहां पर बड़े पैमाने पर मुसहर समुदाय के लोग निवास करते है।

बरसात के दिनों में यहां के लोग करीब चार माह तक घरों में कैद रहने के लिए मजबूर रहते है।

आजादी के बाद से आज तक वह लोग बेहतर सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य सुविधाएं के लिए भटक रहे है। धरना-प्रदर्शन के समर्थन में तीसरे दिन सोहगीबरवा स्थित एक मदरसा के बच्चे मौलाना अनवर की मौजूदगी में मांगों को पूरा करने के लिए अड़े रहे।

इन लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तीन दिनों से धरना चल रहा है, लेकिन कोई उच्चाधिकारी उन लोगों की समस्याओं का सुध लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। उन लोगों की मांग जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक वह लोग धरना प्रदर्शन पर डटे रहेंगे।

शिक्षा है विकास की बुनियाद

पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गरीब छात्रों के लिए निजी मेडिकल कालेजों में लागू 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना' को संवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा दिलाना असंवैधानिक या अनुचित नहीं है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना' की शुरूआत की थी। इसमें सरकारी एवं निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग और ला कालेज में प्रवेश के पश्चात सौ फीसद फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही पुस्तकों, हास्टल फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों में भी मदद की जाती है।

शिक्षा किसी भी देश विकास की बुनियादी तैयार करती है। फिर चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, इनका उद्देश्य देश और समाज के लिए बेहतर नागरिक तैयार करना होता है। इसी कारण शिक्षा को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर अनेक परिवार ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए अपने बच्चों को महंगी होती जा रही शिक्षा दिलाना एक सपने जैसा होता है। गरीबी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफार्म और आवश्यक सामान खरीदने में कठिनाई होती है।

गरीबी कारण बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। गरीब परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के बजाय उनकी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में करीब 1.1 अरब लोग गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। केवल भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगर दुनिया में गरीबी है तो उसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही है। अगर गरीबी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है।

गरीब छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समाज के गरीब, कमजोर वर्गों को शिक्षा देने से देश में बेरोजगारी, निम्न आय और इससे संबंधित कई समस्याओं का समाधान होता है।

शिक्षण शुल्क समय पर जमा नहीं करने के कारण सरकारी योजनाओं को असंवैधानिक और अनुचित बताना कहीं से भी उचित नहीं है।

जब सरकार गरीब छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई योजनाएं ला रही है, तो निजी संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे भी शिक्षण शुल्क के लिए सरकार पर दबाव बनाने के बजाय धैर्य रखें और इस फैसले में उसका साथ दें, ताकि गरीब छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके।

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं बच्चे, आकार देने की जरूरत

महराजगंज। बच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं उन्हें जिस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास होगा वह उसी तरह के बनेंगे। इसलिए स्कूल के शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों में शिक्षा व संस्कार के बीज अंकुरित करें। उक्त बातें बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडेय ने व्यक्त किया। वह कंपोजिट बागापार स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची थीं। स्कूल की शिक्षिका दीपाली पटेल ने पुष्पगुच्छ देकर बीएसए का स्वागत किया।

बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्वागत स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए किया। मल्हार राग सुनाकर बच्चों ने इसकी उपयोगिता का परिचय भी दिया।

महाभारत नृत्य नाटिका, मोबाइल दुष्प्रभाव, निजी स्कूल फीस वृद्धि जैसे ज्वलंत पहलुओं पर नाटक खूब सराहे गए। बीएसए ने अंकपत्र व मोमेंटम देकर बच्चों को उत्साहित कर अगली कक्षा में और परिश्रम की सीख दी। कार्यकाल पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो रहे शिक्षक देवी शरण त्रिपाठी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

बीईओ अंकिता सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ई. विवेक गुप्ता, प्राथमिक शिक्षक संघ सदर अध्यक्ष बैजनाथ सिंह, अखिलेश पाठक, रामचंद्र प्रजापति विशिष्ट अतिथि रहे।

प्रधान बागापार विवेक सिंह व स्कूल के प्रभारी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी शामिल रहे।

महायोजना-2031 मंजूर, शहर में शामिल होंगे 30 गांव 17.4

बांदा। महायोजना-2031 पर शासन ने मुहर लगा दी है। इसमें करीब 3.72 लाख आबादी को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विकास का खाका खींचा गया है। 30 गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर 4360 हेक्टेयर क्षेत्रफल का शहरीकरण किया जाएगा। महायोजना-2031 तैयार करने में करीब साढ़े तीन लगे हैं। शहर के विस्तारीकरण के लिए पहले महायोजना-2021 तैयार कर लागू की गई थी। इसका क्षेत्रफल 2412 हेक्टेयर निर्धारित था। यह महायोजना 2.70 लाख शहरी आबादी के लिए तैयार की गई थी। इसमें आवासीय उपयोग के लिए 1009.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल तय किया गया था। अब महायोजना 2031 करीब 3.72 लाख आबादी के हिसाब से तैयार की गई है। इसमें क्षेत्रफल बढ़ाकर 4360 हेक्टेयर किया गया है। आवासीय उपयोग के लिए इसमें 2352.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रावधान किया गया है। पिछली महायोजना में व्यवसायिक उपयोग के लिए सिर्फ 34.07 हेक्टेयर क्षेत्रफल तय हुआ था। इस बार इसे बढ़ाकर 185.90 हेक्टेयर कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए पहले 103.36 हेक्टेयर भूमि थी, अब नई महायोजना में इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 220.64 हेक्टेयर रखा है। कार्यालयों के लिए पहले 87.34 हेक्टेयर और मनोरंजन सुविधाओं के लिए 411.33 हेक्टेयर का प्रावधान था, जबकि महायोजना 2031 में कार्यालयों के लिए 426.42 और मनोरंजन सुविधाओं के लिए 845 हेक्टेयर जमीन तय है। यातायात व परिवहन के लिए 329 और अन्य भू उपयोग के लिए 264.25 हेक्टेयर की व्यवस्था की गई है।

इन गांवों में बने हैं अमृत सरोवर तालाब

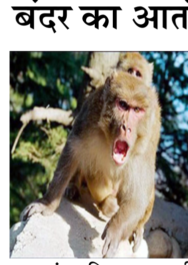
रसूलपुर, भिरावटी, सिहावली, मुटैना गिरधारी, मंडावली, रोरादीप, न्यौरा, देवरा भूरा, उधरनपुर खागी, भीकमपुर जागीर, भीकमपुर जैनी, भैंसरौली, पवसरा, जयदासपुर, बहटकरन, सिकंरपुर खागी, चमरपुरा।

सभी तालाबों का मानसून से पहले जीर्णोद्धार कराकर बेहतर किया जाएगा। इस-के लिए तैयारी की गई है। इसके लिए सभी के साथ बैठक भी की जाएगी।

देवराज सिंह,
एडीओ पंचायत,
रजपुरा।



बंदर का आतंक, भय व्याप्त



कलवारी, बस्ती। राम जानकी मार्ग पर स्थित बहादुरपुर ब्लाक क्षेत्र के आचार्य रामचन्द्र शुक्ल बालिका इंटर कालेज अगौना में एक सप्ताह से बंदर का आतंक है। विद्यालय की छात्राएं व शिक्षक भयभीत रहते हैं। विद्यालय के प्रबंधक डॉ.के पी मिश्र ने बताया कि विद्यालय में बालिकाओं को बंदर से हमेशा भय बना रहता है। यहां तक कि कभी कभार पढ़ाते समय बंदर कक्षा में घुस जाता है तो कक्षा में अफरातफरी मच जाती है। किसी तरह उसे बाहर भगाया जाता है। वह बंदर हमेशा विद्यालय परिसर में ही रहता है। उन्होंने वन विभाग से इसे पकड़वाने की मांग भी की है।

साईं भजन संध्या में देर रात तक झूमते रहे श्रद्धालु

बस्ती। साईं श्रद्धा सबुरी कीर्तन मंडली की तरफ से बुधवार को शहर के रौतापार मोहल्ले में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भक्तों ने श्री साईं बावनी का पाठ किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में श्रद्धालु झूमते रहे। गायक संदीप श्रीवास्तव ने ...मेरे घर के आगे साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए... प्रस्तुत कर माहौल साईंमय कर दिया। इसके अलावा ...थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े चले आएंगे..., नीरज राजा ने ... सुन लो हे मेरे बाबा अब तेरा ही सहारा... भजन प्रस्तुत किया। गायक सुनील श्रीवास्तव ने ...मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे साईं जी आएंगे... प्रस्तुत कर अपनी हाजिरी लगाई।

गर्मी के साथ बढ़ा निमोनिया का प्रकोप



महराजगंज। गर्मी में बच्चे बीमार हो रहे हैं। निमोनिया की वजह से फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। तेज गर्मी, दूषित खाने पीने, धूप से आकर तुरंत ठंडी चीज पीने से यह समस्या हो रही है। जिला अस्पताल में इन दिनों आठ से दस मरीज इस समस्या से पीड़ित आ रहे हैं।

तेज धूप और लू से डायरिया, पेट में दर्द और निमोनिया के मरीजों को दिक्कत बढ़ रही है। जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रंजन मिश्रा ने बताया कि गर्मी और दूषित सामग्री खाने-पीने से डायरिया, धूप से आकर तुरंत ठंडी चीजें खाने-पीने से निमोनिया के मरीज बढ़े हैं। फेफड़ों में संक्रमण की समस्या आ रही है। बीते 8-10 दिन में रोजाना 100 से 150 मरीज ओपीडी और इमरजेंसी में आ रहे हैं। इनमें उल्टी-दस्त, पेट में दर्द, पानी की कमी और पसली चलने की परेशानी मिली। रक्तचाप गड़बड़ाने से घबराहट की भी दिक्कत मिल रही है। राहत की बात है कि इलाज से मरीज ठीक हो रहे हैं। सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी ने बताया कि अस्पताल में बेहतर इलाज का इंतजाम है।

देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने खंगाले स्पा सेंटर्स

चंदौसी (संभल)। मुरादाबाद रोड धन्नूमल तिराहा के निकट चल रहे स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना पर 112 पुलिस और मंडी चौकी पुलिस महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर कुछ नहीं मिला। जिससे पुलिस बैरंग लौट गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

गत दिनों बृहस्पतिवार की शाम चार बजे प्राइवेट बिजलीकर्मी हर्षित कुमार मुरादाबाद रोड धन्नूमल तिराहा के पास स्पा सेंटर में देह व्यापार होने की सूचना डायल 112 को दी। उसने कहा कि स्पा सेंटर में इस समय 4-5 युवक व युवतियां मौजूद हैं। सूचना के बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला पुलिसकर्मी न होने की वजह से कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मंडी चौकी पुलिस महिला पुलिसकर्मी के साथ पहुंची और स्पा सेंटर में छानबीन की, लेकिन वहां युवक और युवतियां नहीं मिलीं। लड़कियों के कपड़े पड़े हुए थे। स्पा सेंटर संचालक ने आरोपों को निराधार बताते हुए पुलिस को बताया कि बिजली कर्मी यहां आकर बेवजह झगड़ा करने लगा।

स्पा सेंटर में युवक-युवतियों के होने की सूचना 112 पुलिस को मिली थी। पुलिस को मौके से कुछ नहीं मिला है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं।

-मोहित चौधरी,
प्रभारी निरीक्षक, चंदौसी

मनरेगा एक बहुआयामी योजना : ग्रामीणों की खुशहाली के लिये मनरेगा का सशक्तिकरण हो

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है, इन सिफारिशों से न केवल यह योजना अधिक सशक्त एवं प्रभावी होकर ग्रामीण जनजीवन के कमजोर लोगों के लिये राहत का माध्यम बनेगी, बल्कि ग्रामीण जीवन को नये भारत की बुनियाद बनायेगी। मनरेगा भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीब एवं कमजोर लोगों के लिए उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है और वर्तमान में यह भारत में सबसे बड़ा स्व-लक्ष्यीकरण कार्यक्रम है। यह सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावशाली साधन है। जो नये भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत का आधार होगा। मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था है, बावजूद मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अफसरशाही, अनियमितता, कोताही के कारण इस महत योजना पर भी समय-समय अंधेरा छाता रहा है। यों तो गिरावट हर स्तर पर है। समस्याएं भी अनेक मुखरित हैं पर राष्ट्रीय चरित्र को विघटित करने वाले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की काली छाया मनरेगा पर न पड़े, इसलिये स्थायी समिति का यह सुझाव स्वागतयोग्य है कि श्रमिकों की संतुष्टि, वेतन में देरी, भागीदारी के रुझान और योजना में वित्तीय अनियमितताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसीलिये समिति ने मनरेगा से जुड़े कार्यक्रम की कमियों के बारे में अहम जानकारी प्राप्त करने और मनरेगा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए देशभर में स्वतंत्र एवं पारदर्शी सर्वेक्षण की सिफारिश की है। समिति ने उभरती चुनौतियों के मद्देनजर योजना को नया रूप देने पर भी जोर दिया है। मनरेगा बदलते वक्त और उभरती चुनौतियों के बावजूद आज भी प्रासंगिक है।

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है, जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, यह योजना टिकाऊ संपत्तियां जैसे सड़क, नहर, तालाब, कुएं बनाने पर जोर देती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान करती हैं। भारत आज भी गांवों का देश है, विकास की गंगा गांवों से होकर ही निकलती है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अन्य रोजगार के अवसर सीमित हैं, यह श्रम शक्ति के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है, जिससे वे सशक्त हो पाती हैं और समाज में सक्रिय भूमिका निभा पाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को मनरेगा के तहत 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। मनरेगा एक बहुआयामी योजना है, जिसके तहत विभिन्न उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें, और अन्य बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को रोजगार का दावा करने का अधिकार है। इस दूरगामी एवं ग्रामीण जनजीवन के उन्नयन एवं उत्थान के कार्यक्रम के लागू होने के बाद लाखों मजदूरों को काम मिला है। पलायन में काफी हद तक कमी आई। मनरेगा ने साबित किया कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वह आज भी उम्मीद की किरण है। इस कार्यक्रम से लाखों अकुशल श्रमिकों और महिलाओं को पूरे वर्ष में सौ दिन के रोजगार की गारंटी मिली।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 नवाचार श्रेणी के लिए चयनित शासकीय अधिकारियों की सूची जारी



भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने नवाचार श्रेणी के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 चयनित शासकीय अधिकारियों की सूची जारी की है। सूची में छह क्षेत्रों के लिए 14 शासकीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सभी चयनित शासकीय सेवकों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1-1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। अधिकारियों को यह पुरस्कार अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचार के लिए दिया जा रहा है। सम्मान समारोह का आयोजन नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में किया जाएगा।

शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण, अधोस्-ंरचना, नागरिक सेवा प्रदाय-सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन, रोजगार एवं आर्थिक विकास क्षेत्रों में नवाचार के लिए पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पुरस्कार के चयनित अधिकारियों में शीला दाहिमा, माधव प्रसाद पटेल, अदिति गर्ग, डॉ. इंदिरा दांगी, शारदा डुडवे, आलोक पौराणिक, चंद्रमोहन ठाकुर, डॉ. यशपाल सिंह, संजय जोशी, अमित तोमर, ऋषव गुप्ता, गणेश शंकर मिश्रा, दिव्यांक सिंह और प्रवीण सिंह के नाम शामिल हैं।



नई सरकार ने यमुना के लिए ठोस योजना नहीं बनाई

कड़वा सच तो यह है कि यमुना के दर्द से जब जनता बेपरवाह हुई और महज छठ के आसपास इसकी याद आने लगी तो राजनीतिक दलों ने भी इसे गम्भीरता से लेना छोड़ दिया। यह समझना होगा कि बीते दो दशकों से दिल्ली में हरियाणा से दिल्ली आने वाली यमुना में साल में कम से कम 10 बार अमोनिया की मात्र बढ़ती है। यह भी समझना होगा कि साल दर साल यमुना में पानी की मात्रा कम हो रही है, जबकि उसके किनारे बसे शहरों-बस्तियों की आबादी बढ़ रही है। जाहिर है कि वहाँ से निकलने वाले जल-मल में भी वृद्धि हो रही है और कड़वा सच यह है कि यह आधे अधूरे ट्रीट्मन्ट के बाद यमुना में मिल रहा है। एक तरफ हम यमुना से ज्यादा पानी ले रहे हैं, दूसरा हम इसमें अधिक गंदगी डाल रहे हैं, तीसरा इसमें पानी कम हो रहा है। वैसे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस साल यमुना के मद में 500 करोड़ का प्रावधान रखा है लेकिन कोइ ठोस योजना प्रस्तुत की नहीं।

दिल्ली में यमुना पर सफेद झाग छाए थे। थोड़ा करीब से देखा तो पानी निपट काला था। बदबू तो थी ही। खासकर कालिंदी कुंज पर तो लगता था कि यह नदी नहीं, बर्फ का ढेर हो। दिल्ली विधान सभा चुनाव में यमुना को साफ करने के मुद्दे पर खूब चर्चा हुई, होनी भी चाहिए थी क्योंकि केजरिवल सरकार ने इस बारे में बहुत से दावे किए लेकिन नतीजा सिफर रहा था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब चुनावी नतीजे आते ही, बगैर सरकार के गठन के यमुना में कुछ ऐसी मशीन तैरती दिखीं जो कचरा साफ कर रही थी। हालांकि इस तरह की मशीन दिखावटी अधिक होती है क्योंकि ऐसा कचरा तो यदि कोइ भी नदी अविरल रहे और उसमें बरसात के दिनों में दो-चार बाढ़ आ जाये तो खुद ब खुद किनारे लग जाता है। बीजेपी की दिल्ली की सरकार की यमुना को ले कर नियत पर शक कि शुरूआत उसी समय हो गई थी। सभी जानते हैं कि दिल्ली में आधा राज तो लपटन साब अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर का चलता है। फिर यह मशीन उतारने के लिए सरकार बदलने का ऐन्टजार क्यों किया गया ?

लेकिन यमुना की जमीनी हकीकत को परे रख कर जिस तरह अहमदाबाद के साबरमती फ्रन्ट की तर्ज पर दिल्ली की यमुना को दमकाने कि योजनाएं सरकार के खजाने से बाहर आई उससे जाहिर हो गया कि यमुना में निर्मल जल और विशाल जल निधि के बनिस्पत उसकी भूमि छुड़ा कर उसका व्यावसाईक इस्तेमाल करना सरकार की मंशा है। वैसे एन जी टी सन 2015 में ही दिल्ली के यमुना तटों पर निर्माण पर पाबंदी लगा चुका है लेकिन इससे बेपरवाह सरकारें मान नहीं रही। अभी एक साल के भीतर ही लाख आपत्तियों के बावजूद सराय कालेखान के पास ह्वबांस घरह्व के नाम से केफेटेरिया और अन्य निर्माण हो गए। और अब यही सराय काले खान के सामने 22 एकड़ का जो रिवर फ्रन्ट बनाने की बात है, वह भी एन जी टी के आदेश की खुली अवहेलना ही होगा।

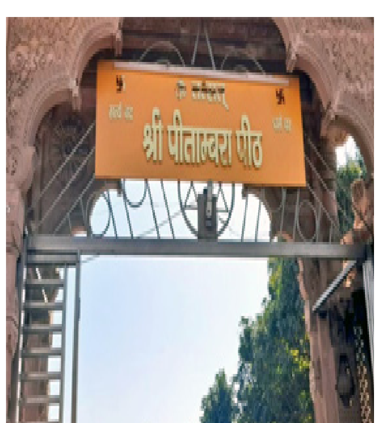
▸ मां पीताम्बरा धाम के विकास को मिली 44.24 करोड़ की सौगात

दतिया बनेगा आध्यात्मिक पर्यटन का हब

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां पीताम्बरा की नगरी दतिया को प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत पीताम्बरा पीठ और उससे जुड़े क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 44.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि मंदिर परिसर के आधुनिकीकरण, श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में उपयोग की जाएगी।

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस योजना के तहत ब्रीदिंग स्पेसेज, मल्टी-लेवल कार पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाओं, स्मार्ट डिस्प्ले, संकेतक बोर्ड, इंटरप्रिटेशन सेंटर और फुटपाथों का निर्माण/पुनर्विकास किया जाएगा। मंदिर के उत्तर द्वार के पास एक हजार वर्ग मीटर में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी श्रद्धालुओं को दी जाएगी।

ग्वालियर और झांसी से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हनुमान चौक और बम-बम भोले चौक पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रोटरी सिस्टम बनेगा। साथ ही फुटपाथों को चौड़ा और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे पैदल श्रद्धालुओं को सुविधा हो। मल्टी-लेवल पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों की व्यवस्था होगी और भविष्य में इसे मंदिर के पाथवे से जोड़ा जाएगा।



इस योजना से न केवल मंदिर परिसर सुंदर और सुव्यवस्थित होगा बल्कि दतिया को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी नई पहचान मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ओंकारेश्वर और अमरकंटक को भी प्रसाद योजना के तहत क्रमशः 44.81 करोड़ और 50 करोड़ की सहायता मिल चुकी है। सरकार का लक्ष्य माँ पीताम्बरा पीठ को श्रद्धा और आधुनिकता का संगम बनाकर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में स्थापित करना है।

धरोहर संकल्प-2025 : एक दिवसीय विरासती प्रदर्शनी

गोरखपुर (जीकेबी)। दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन फार आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज व महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ दीदउ गोविवि के संयुक्त तत्वावधान में विभ धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित धरोहर संकल्प-2025 (भारतीय संस्कृति और विरासत का वैभव) एक दिवसीय विरासती प्रदर्शनी, संवाद सांस्कृतिकी कार्यशाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ परिसर में किया गया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय में अपनी धरोहर की रक्षा करना नागरिक समाज का प्रथम कर्तव्य है। पारिवारिक संस्कार और मूल्यों के साथझसाथ संस्कृति के संरक्षण में विरासत और धरोहर अहम भूमिका निभाते हैं।

बतौर विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के बीच में निरंतर होते रहने चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने कहा कि यह दिन केवल स्मृति का नहींङ्क अपितु संकल्प का भी है। कार्यक्रम के संयोजक महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ के उपनिदेशक डा. कुशलनाथ मिश्रा ने कहा कि धरोहर हमारे अतीत को वर्तमान से जोडक्ने का काम करती है।

कार्यक्रम के आयोजन सचिव और राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल डा. संदीप कुमार श्रीवास्तव ने आयोजन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ऐसे आयोजनों को भविष्य में और बेहतर तरीके से करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सांस्कृतिकी और सम्मान से सुसज्जित रहा समापन सत्रः कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के



रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विभविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत देश अपनी समृद्ध परंपराओ अनेक कलाओं और बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत के लिए विभभर में प्रसिद्ध है।

विशिष्ट अतिथि दीदउ गोरखपुर विभविद्यालय की अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने कहा आज हम आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तब यह बहुत आवश्यक है कि ऐसी प्रदर्शनी आयोजित कर समाज को संदेश देने का कार्य किया जाए। महायोगी गुरु गोरखनाथ विभविद्यालय के सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रेरणादायी प्रयास है जहां हम अपने युवाओं को यह संदेश दे सकते हैं कि धरोहर केवल ईट-पत्थर नहीं बल्कि हमारी आत्मा हैं। समापन सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई।

कार्यक्रम में धरोहरों का संरक्षण करने वाले नागरिक समाज के लोगों का सम्मान किया गया। इनमें विनय गुप्ता, तृप्ति श्रीवास्तव, निलय कुमार को धरोहर सृजन सम्मान। विभमोहन तिवारी, संदीप चौरसिया, अचिंत्य लाहिड़ी, वेद प्रकाश सिंह, पूजा सिंह, अनुपम सहाय, डा. विन्रम शर्मा, मून श्रीवास्तव, प्रियंका श्रीवास्तव को धरोहर श्री प्रशस्ति सम्मान। स्टेट बैंक आफ इंडियाङ्क होम कलेनस लाइब्रेरी, नगर निगम, महात्मा गांधी इंटर कालेज, सेंट एंड्रयूज कालेज को धरोहर रक्षक सम्मान। धीरज सिंह, अनिल सिंदूर, धीरज श्रीवास्तव, डा. राजेश चंद गुप्ता, शोभित श्रीवास्तव, रीना जायसवाल, शिवम सिंह, रीता श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, शारदानंद पांडेय, गौरव गुप्ता, ज्योति श्रीवास्तव, नवाज अहमद, स्निग्धा सिंह, बृजनंदन श्रीवास्तव को धरोहर निष्ठा सम्मान से सम्मानित किया गया।

उद्घाटन सत्र का संचालन एड. शुभेंद्र सत्यदेव ने और समापन सत्र का संचालन डा. हर्षवर्धन सिंह एवं रीता श्रीवास्तव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन के ट्रस्टी डा. संदीप कुमार श्रीवास्तव ने किया।

सम्मान सभा में भाजपाइयों ने किया बाबा साहब का गुणगान

बस्ती। विकास क्षेत्र साऊंघाट की ग्राम पंचायत हड़िया में भाजपा की तरफ से डॉ. भीमराव आंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब को सम्मान मिले। साजिश करके उन्हें चुनाव हरवा दिया जाता था। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार बाबा साहब की हर धरोहर को संरक्षित कर रही है। बाबा साहब के नाम से कई योजनाएं चलाकर सभी को रोजगार, शिक्षा व आत्म निर्भर भी बना रही है। गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल, हरैया विधायक अजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि बाबा साहब के अतुलनीय योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता। अन्य पार्टियों ने बाबा साहब का नाम लेकर लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। वहीं भाजपा सरकार ने बाबा साहब के सम्मान में कोई आंच आने नहीं दिया। पूर्व विधायक रवि सोनकर, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान के निर्माण तक बाबा साहब का विशेष योगदान हैं। संचालन करते हुए ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार ने सभी मेहमानों को स्मृति चिह्न भेंट कर आभार प्रकट किया।

गुड फ्राइडे : गिरिजाघरों में इसाई समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, की विशेष प्रार्थना

गोरखपुर (जीकेबी)। पूरी दुनिया को शांति व एकता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के बलिदान दिवस गुड फ्राईडे. पर नगर के सभी गिरिजाघरों में इसाई समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में भक्तिभाव से सहभागिता की। इस दौरान धार्मिक गीत भी हुए और विश्वासियों ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया।

सेंट जोसेफ महा गिरजाघर में आयोजित कार्यक्रम में फादर जीजो एंथोनी के नेतृत्व में क्रूस का जुलूस निकाला गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मुक्ति दाई बलिदान के दिवस को अस्मरण करने वाली धार्मिक पूजन विधि पुरोहितों के साथ प्रारंभ करते हुए प्रार्थना की गई। गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर जीजो एंथोनी ने बताया कि आज शुक्रवार है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिया।

सेंट एंथोनी चर्च धरमपुर में मुख्य याजक फादर सिबीचन के नेतृत्व में क्रूस के रास्ते जुलूस निकला। फादर जेस्टिन व फादर एविन ने अपने संदेश में बताया कि आज के दिन प्रभु यीशु ने मानव मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए।

सेंट जांस चर्च बशारतपुर में सामूहिक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रभु यीशु के बलिदान को याद कर चर्च के प्रेसबिटर इंचार्ज रोशन लाल ने अंतिम वाणी पर प्रकाश डालते हुए बताया- हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सोता हूं'। मुख्य वक्ता गाजियाबाद से आए अनिल मसीह ने कहा कि चर्च में जीवन मिलता है मौत नहीं मिलता। मां के प्रेम को पहचानिए। शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में यीशु मसीह के क्रूसीकरण को दशार्ती लघु डाक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस अवसर पर प्रभु येशु मसीह के क्रूस से कहे अंतिम सात वचनों पर विभिन्न वक्ताओं ने प्रकाश डाला।

कानपुर से पधारे पास्टर अमित डिकोस्टा ने पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन साझा किया। प्रेसबिटर इंचार्ज रेव्ह. ड़ी.आर. लाल ने बताया कि आज से लगभग दो हजार साल पहले परमेभर के इकलौते पुत्र ने क्रूस पर अपना बलिदान दे कर संपूर्ण मानवजाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया था।

इस दौरान ड़ा. एस.के. लारेंसङ्क अमर ज्वाय सिंह समेत चर्च के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। सेंट मार्क चर्च में प्रेसबिटर इंचार्ज रेव्ह संजय विंसेंट ने आराधना सभा का संचालन किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए साथ वचनों पर विस्तृत प्रकाश डाला। चर्च के सचिव अमित राबर्ट व खजांची अंकित जान ने चर्च में आये हुए सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही असेंबली आफ बिलीवर चर्च राप्ती नगर, फुल गोस्पल चर्च मोती पोखरा, पीस टर्बिनिकल चर्च मयूर विहार, मसीही कलीसिया चर्च खरैया पोखरा, यूनियन चर्च खजांची बाजार, सेंट एंड्रयूज चर्च रेलवे कालोनी कौवा बाग, सेंट थामस चर्च धर्मपुर, सेंट एंथोनी चर्च धर्मपुर, कार्मल माउंट चर्च पादरी बाजार सहित महानगर और उससे बाहर के क्षेत्रों के गिरिजाघरों में आराधना सभा का आयोजन हुआ। प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार को सूली दी गई थी। उसके तीसरे दिन रविवार को वह जी उठे थे। इस दिन को विश्वासी ईस्टर डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी गिरजाघरों में विश्व शांति के लिए प्रार्थना व मंगल कामना की जाएगी। ईस्टर के कार्यक्रम व प्रार्थना शनिवार से ही प्रारंभ हो जाएंगे।



चॉक से चुभता शोषण: प्राइवेट स्कूल का मास्टर और उसकी गूंगी पीड़ा

प्राइवेट स्कूल का मास्टर: सम्मान से दूर, सिस्टम का मजदूर

प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों से उम्मीदें तो आसमान छूती हैं, लेकिन उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है, न सम्मान, न छुट्टी और न ही सुरक्षा। महिला शिक्षक दोहरी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं, वहीं शिक्षक दिवस के दिन सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान मिलता है जबकि सालभर उनका शोषण जारी रहता है। अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकार तीनों ही इस शोषण को नजरअंदाज करते हैं। शिक्षक के अधिकारों की कोई बात नहीं करता, न ही कोई नियामक संस्था है जो उनके हितों की रक्षा करे। शिक्षकों को कानूनी संरक्षण, संगठित मंच और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली सच में समावेशी और न्यायपूर्ण बन सके। यदि राष्ट्र को शिक्षित और सशक्त बनाना है, तो सबसे पहले शिक्षक को शोषण से मुक्त करना होगा—क्योंकि चॉक से लिखा हर अक्षर, देश का भविष्य गढ़ता है।



एक समय था जब गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय जैसे दोहे बच्चों की जुबान पर होते थे। आज हाल ये है कि अगर मास्टर जी मोबाइल पकड़ लें तो कहा जाता है इतनी फुर्सत है तो बच्चों को क्यों नहीं संभालते? जमाना बदल गया है, अब 'शिक्षक' शब्द पवित्रता नहीं, सहनशीलता का प्रतीक बन गया है। और इस सहनशीलता का सबसे क्रूर रूप दिखता है—प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की दुनिया में।

दिखावे का महल भीतर हताशा का दलदल

बाहर से देखिए तो प्राइवेट स्कूल किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगता—एसी क्लासरूम, हाईटेक बोर्ड, इंग्लिश बोलते बच्चे और व्हाइट-ग्लव्स पहने बस अटेंडेंट्स। लेकिन अंदर झाँकिए, वहाँ एक मास्टर साब बैठा है, जो न वक्त पर चाय पी सकता है, न लंच कर सकता है। जो बच्चा होमवर्क न करे, उसकी शिकायत आए तो मास्टर की क्लास लगती है। जो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, तो मैनेजमेंट पूछता है—क्यों पढ़ाया नहीं ढंग से?

तनख्वाह: जो कागज पर है, जेब में नहीं

प्राइवेट स्कूलों में सैलरी का सिस्टम इतना गोपनीय है कि सीक्रेट एजेंसियाँ भी शर्मा जाएं। अपॉइंटमेंट लेटर पर ₹25,000 लिखा होता है, लेकिन बैंक में ₹8,000 ट्रांसफर होते हैं। बाकी कैश में मिलते हैं या कभी नहीं मिलते। और मजा देखिए—टीचर से सैलरी का हिसाब माँगा जाए तो जवाब होता है: बोलिए, नौकरी चाहिए या नहीं?

महिला शिक्षकों का दोहरा शोषण

घर में बहू, माँ और पत्नी। स्कूल में मैडम, टीचर और दीदी। महिला शिक्षकों को दोहरी ज़िम्मेदारी के साथ जीना पड़ता है। सुबह 5 बजे से घर संभालो, फिर स्कूल जाओ और वहाँ 40 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। ऊपर से अगर पति भी प्राइवेट सेक्टर में हो, तो महीने की सैलरी से पहले ही घर का बजट गिरवी रख देना पड़ता है।

छुट्टी? वो तो सपना है!

सरकारी कैलेंडर कहता है—15 अगस्त छुट्टी है, 26 जनवरी छुट्टी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल कहता है—ह्लआओ, झंडा फहराओ, भाषण दो, फिर हाजिरी लगाओ और जाओ।ह्व छुट्टी के दिन भी हाज़िरी की मजबूरी।

अगर बीमार पड़ गए, तो ल्फकहेगा—₹छुट्टी नहीं है, डिडक्शन लगेगा।₹ शिक्षक का गला बैठ जाए, तब भी कहा जाता है—ह्लक्लास तो लेनी होगी, और कोई नहीं है।ह्व

काम का बोझ और भावनात्मक शोषण

आज शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो क्लास टीचर है, परीक्षा नियंत्रक है, अभिभावक संवाद अधिकारी है, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है, स्पोर्ट्स डे का आयोजक है और हर हफ्ते सेल्फी वाले वीडियो का संपादक भी। लेकिन जब सैलरी की बात आए, तो कहा जाता है—आप तो सिर्फ दो पीरियड पढ़ाते हैं।

मास्टर के आंसू और प्रिंसिपल का प्रेस कॉन्फ्रेंस

बच्चा अगर टॉप करे तो प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है—ह्लहमारे स्कूल का वातावरण ही ऐसा है।ह्व और अगर बच्चा फेल हो जाए तो मास्टर की जवाबदेही तय होती है—ह्लआपने ठीक से पढ़ाया नहीं।ह्व जीत स्कूल की, हार शिक्षक की। फोटो बैनर पर प्रिंसिपल की, मेहनत मास्टर की।

पैरेंट्स की उम्मीदें: टीचर या जादूगर?

आजकल अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षक 3 महीने में उनके बच्चे को आईएएस बना दे, और अगर ऐसा न हो पाए तो कहते हैं—ह्लहम तो सरकारी स्कूल में डाल देते तो भी क्या फर्क पड़ता!ह्व बच्चे की गलती भी अब मास्टर की जिम्मेदारी है। पैरेंट्स मीटिंग में सबसे ज्यादा डांट मास्टर खाता है।

शिक्षक दिवस: एक दिन की इज्जत, साल भर की जिल्लत

5 सितंबर को बच्चों से ₹हैप्पी टीचर्स डे₹ के फूल मिलते हैं। बच्चे गाना गाते हैं—₹सर आप महान हैं₹ और अगले ही दिन वही बच्चा होमवर्क न करने पर कहता है—टीचर का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं।₹ साल भर की जिल्लत को एक दिन की इज्जत से ढकना, अब आदत बन गई है।

कानून कहां है? शिक्षा नीति सिर्फ कागज पर

नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि शिक्षक की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि न कोई रेगुलेशन है, न कोई निगरानी। जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ सरकारी स्कूलों की जांच करता है, प्राइवेट स्कूलों को छूट मिली हुई है—₹अपना नियम खुद बनाओ, खुद चलाओ।₹

छात्र और शिक्षक: एकतरफा रिश्ता

आज छात्र अधिकारों की बात करता है—मार नहीं खाना, होमवर्क कम मिलना, रिजल्ट अच्छा आना। लेकिन शिक्षक के अधिकारों की बात कौन करे? क्या कोई पळकलगा सकता है कि मास्टर को कितनी सैलरी मिल रही है? नहीं। क्योंकि शिक्षक अधिकारों की बात करना आज भी ₹असहनीय₹ माना जाता है।

समाधान: मौन नहीं, आंदोलन चाहिए

अब वक़्त आ गया है कि शिक्षक चुप्पी तोड़े। सरकार को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो प्राइवेट स्कूलों की सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियाँ और काम का बोझ तय करे।

हर जिले में निजी शिक्षकों की यूनियन बने जो एक स्वर में बोले। अभिभावकों को भी समझना होगा कि शिक्षक सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि उनके बच्चे के भविष्य का निमार्ता है।

थोड़ा सम्मान, थोड़ा अधिकार इतनी सी बात

देश अगर आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उस हाथ को संभालना होगा जो ब्लैकबोर्ड पर चॉक से भविष्य रचता है। उस आवाज को सुनना होगा जो हर दिन गुड मॉर्निंग कहकर बच्चे को दिन की शुरूआत सिखाता है। शिक्षक की मुस्कान में देश की मुस्कान छिपी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द है, ये जानने वाला कोई नहीं। बच्चा फेल हो जाए तो शिक्षक जिम्मेदार। बच्चा टॉप कर जाए तो स्कूल का नाम। ये संतुलन तोड़ना होगा। अगर प्राइवेट स्कूलों को सचमुच शिक्षा का मंदिर बनाना है, तो पहले उसमें शिक्षक की पूजा होनी चाहिए—कम से कम उसका शोषण तो बंद हो।

प्रियंका सौरभ

कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका व चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही भारत आज विश्व में सबसे अधिक तेज गति सेआगे बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है, परंतु इसके आगे की राह अब कठिन है क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है तथा कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा। भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, परंतु आज भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु आज इस समस्या को बहुत हद तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है तथा इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने में सफलता मिली है।भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। जिससे यह किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं,इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इस तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में,मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है।

भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे है अन्यथा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है, इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि उत्पादों की बबार्दी को रोकने में सफलता मिल रही है।

खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी



हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद की ओर से एक निजी कंपनी के साथ मिल कर तैयार की गई रपट में बताया गया है कि देश के कृषि कार्यबल में 64.4 फीसद महिलाएं हैं, लेकिन सिर्फ छह से दस फीसद महिलाएं कृषि और इससे संबंधित शीर्ष कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं। इस रपट ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और शीर्ष पदों पर उनकी कम उपस्थिति के बीच गहरी खाई को उजागर किया है। रपट के मुताबिक कृषि व्यवसाय का भविष्य महिलाओं को शिक्षा, को शिक्षा, कार्यस्थलों समावेश बढ़ा कर और नेतृत्व विकास के माध्यम है। रपट में यह सशक्त बनाने में निहित आया है कि कृषि शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं का 30-40 फीसद नामांकन ही होता है, लेकिन इनमें से बहुत कम औपचारिक कृषि क्षेत्र में रोजगार पाती हैं। इसलिए कृषि में महिलाओं के करने की जरूरत है। उनकी सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने की समान भागीदारी समर्थन करने से ही कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाया जा सकता है। तभी इसका लाभ समाज सभी सदस्यों को मिल सकेगा। रपट के हवाले से विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी । होगी। मगर उच्च शैक्षणिक स्तर केबावजूद मजबूत औपचारिक रोजगार में उनकी संख्या नगण्य है। इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। रपट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां सुझाई हैं। इनमें महिलाओं को संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देकर उनको नेतृत्व के लिए प्रेरित करना शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कृषि परिदृश्य एक आश्चर्यजनक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। महिलाएं कृषि कार्यबल और शैक्षिक समूहों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी स्नातकों एक बड़ा हिस्सा औपचारिक रोजगार संरचनाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। हमें इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए समाधान के रास्ते खोजने होंगे। असल में, कृषि में स्त्रियों की भागीदारी बहुआयामी प्रक्रिया है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। कृषि में महिलाओं की पूर्ण और बराबर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के कड़ों के अनुसार, भारत में कृषि श्रम बल में महिलाएं महत्त्वपूर्ण अनुपात में हैं। वर्ष 2010-11 की अवधि में लगभग 43 फीसद किसान और 52 फीसद कृषि मजदूर महिलाएं थीं। मगर समय साथ कृषि श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। वर्ष 2002- -03 में महिला कृषकों का अनुपात 37 फीसद से बढ़ कर वर्ष 2010-11 में 43 फीसद हो गया। इसी अवधि में महिला कृषि मजदूरों 1143 का अनुपात 48 फीसद से बढ़ कर 52 फीसद हो गया। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा कृषि में अहम भूमिका निभाई है, चाहे वे किसान हों या मजदूर। हालांकि उनके योगदान को अक्सर अनदेखा किया और कम करके आंका जाता है। उन्हें इस क्षेत्र में समान भागीदारी और निर्णय लेने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारकों में से एक, इस क्षेत्र में पुरुष श्रम शक्ति में गिरावट है। यह गिरावट कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें कृषि का मशीनीकरण, गैर-कृषि रोजगार में बदलाव और बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पुरुषों का शहरी क्षेत्रों में पलायन शामिल है। नतीजतन, महिलाओं ने कृषि में अधिक से अधिक जिम्मेदारियां और भूमिकाएं निभानी शुरू की हैं।

महिलाओं के बढ़ते योगदान को अब कम करके आंका नहीं जा सकता। उनको यह मान्यता विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और सरकारी पहलों संभव हुई है। खेती में स्त्रियों की भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़ी है। हालांकि उन्हें अब भी कृषि में समान भागीदारी के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि में भूमि और अन्य संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच अक्सर पुरुषों की तुलना में सीमित होती है। वर्ष 2010- 11 की अवधि में भारत 1 में केवल 13 फीसद महिला कृषकों के पास खेती की जमीन थी, जबकि 37 फीसद पुरुष कृषकों के कपास खेती की जमीन थी। यह असमानता अन्य संकेतकों में भी। दिखाई देती है, जहां महिलाओं की विस्तार सेवाओं और विपणन तक पुरुषों की तुलना में कम पहुंच है।इस क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियों में भेदभाव और रूढ़िवादिता भी है, जो इस क्षेत्र में संसाधनों, ज्ञान और अवसरों तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करती है। इनका समाधान करने और खेती में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक है, जो जो इस क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं। इसमें ऐसी पहलें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य संसाधनों, ज्ञान और व तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करते हुए लोगों की पुरानी सोच को बदलना है। इसके लिए नागरिक समाज भी कृषि क्षेत्र की महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित करने, उन्हें उनके सभी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, विस्तार सेवाओं उनकी पहुंच को सक्षम तक 1 और उन्हें स्थायी आजीविका ₹बनाने प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए महिलाओं को भूमि और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना होगा, जिसमें ऋण, विस्तार सेवाएं और भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। । कृषि में महिलाओं के अवैतनिक और अनौपचारिक श्रम की मान्यता तथा मूल्य को बढ़ावा देना जरूरी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों सहित कृषि में महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को समर्थन देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना होगा।

किसान संगठनों, सहकारी समितियों और अन्य स्थानीय संस्थाओं सहित सभी स्तरों पर र निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। तकनीकी सहायता और वित्त पोषण के प्रावधान माध्यम से कृषि में महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों और उद्यमों के विकास का समर्थन करना होगा। महिलाओं के भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना होगा, ताकि उन्हें विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सके निस्संदेह कृषि में महिलाओं की भूमिका अहम है। वे खेती संबंधी कई काम करती हैं, जैसे बीजों का चयन, खेतों की जुताई, फसलों की कटाई, मवेशी प्रबंधन, दूध दुहना, चारा इकट्ठा करना आदि। उनकी भागीदारी दर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है। मगर समानता को बढ़ावा देने और क्षेत्र की स्थिरता तथा उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों की भूमिका बढ़ाई जाए। उनकी समान भागीदारी का समर्थन कर कृषि क्षेत्र को समृद्ध किया जा सकेगा। वहीं महिलाएं कृषि और इससे संबंधित शीर्ष कंपनियों में नेतृत्वकारी पदों पर पहुंच पाएंगी। कृषि क्षेत्र साथ ही देश के विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसके लिए हम सभी को मिल कर काम करना होगा। सरकार के साथ समाज भी जब ऐसे कार्यक्रमों के लिए आगे आएगा, तभी देश का संपूर्ण विकास संभव है। इस विकास को हमें क्रियाशील बनाना ही होगा।

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

बुझे-बुझे सारे अहसास

रंगहीन बना अब जीवन
उमंग रहित है अब मन
जीवन से ना कोई आश
बुझे-बुझे सारे अहसास

ख्वाबो के महल भी टूटे
जग के झूठे भ्रम भी टूटे
कैसे हो फिर से विश्वास
बुझे-बुझे सारे अहसास

स्वार्थी हर रिश्ते - नाते है
पैसे हो तभी सब भाते है
पैसे से बनते रिश्ते खास
बुझे-बुझे सारे अहसास

महाभारत सा यह जीवन
सकुनी बना जब हर जन
शांति का नहीं कोई आश
बुझे-बुझे सारे अहसास

तमस मे प्रमेश दीप जला
मन से अब मन को मिला
बनेगी जीवन फिर खास
सुखद होंगे सब अहसास



प्रमेशदीप मानिकपुरी
आमाचानी धमतरी छ ग

आधी सच्चाई का लाइव तमाशा: रिश्तों की मौत का नया मंच

घर के अंदर की बातें अब घर के नहीं रहीं। एक वक़्त था जब दीवारों के भीतर जो होता था, वही दीवारों में दफन होता था। पर अब दीवारें भी वाई-फाई से जुड़ चुकी हैं और रिश्ते डेटा पैक पर टिके हैं। बात-बात पर फेसबुक लाइव, इंस्टा स्टोरी, और यूट्यूब व्लॉग – यही अब नए जमाने का रिश्ता-निपटान मंच बन गए हैं। कोई थोड़ा-बहुत झगड़ा हुआ नहीं, लोग कैमरा ऑन करके ह्लऑडियंसह्व के सामने आंसू बहाने लगते हैं। और उस रोते चेहरे के पीछे कितनी सच्चाई है, इसका किसी को अंदाजा नहीं होता – क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू अक्सर बेमौसम आता है, या कभी आता ही नहीं।

रोते हुए लाइव, और सहानुभूति का सैलाब

आजकल रिश्तों में सहनशीलता नहीं, स्क्रिप्टिंग आई है। जैसे ही किसी झगड़े या मनमुटाव की चिंगारी उठती है, लोग अपने कैमरे चालू कर लेते हैं और लाइव आकर खुद को पीड़ित घोषित कर देते हैं। आवाज में कंपकंपी, आंखों में आंसू, और शब्दों में दर्द – सब कुछ इतना रियल होता है कि देखने वाला पल भर में 'इमोशनल इन्वेस्ट' कर बैठता है।

पर सवाल ये है कि क्या वो सच्चाई का पूरा चेहरा देख रहा है, या बस आधा?

आज की मिसाल लीजिए – सोशल मीडिया पर पहले 'सुट्टा आली' प्रकरण छाया रहा और अब 'मुक्का वाली' मामला। दोनों में ही एक पक्ष ने पहले सोशल मीडिया पर आकर सहानुभूति बटोरी। लोग टूट पड़े समर्थन में, ट्रोलिंग शुरू हुई, इल्जामों की झड़ी लग गई। लेकिन जब कुछ समय बाद दूसरा पहलू सामने आया, तो वही हमदर्द दोराहे पर खड़े दिखे। कोई खिसियाया, कोई चुप हो गया, और कुछ ने हाथ जोड़ लिए – हमें तो पूरी बात पता ही नहीं थी।

सोशल मीडिया: इंसाफ का नया अदालत?

अब सवाल उठता है – क्या सोशल मीडिया कोई अदालत है, जहां एकतरफा सबूत पेश करके दूसरे पक्ष को बिना सुने सजा सुनाई जा सकती है? क्या हम सब यूजर्स अब जज बन चुके हैं? और अगर हां, तो हमारी अदालत में अपील की व्यवस्था कहां है?

दिक्कत ये है कि आजकल लोग जज नहीं, जजमेंटल बन चुके हैं। किसी भी मुद्दे को बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांचे – बस वायरल होने की स्पीड से नापते हैं। 'कौन सही है' से ज्यादा अहम हो गया है 'कौन पहले लाइव आया'।

रिश्ते अब रील और रेटिंग का हिस्सा बन गए हैं

जब एक रिश्ते की दरार को सार्वजनिक किया जाता है, तो उसका असर केवल उस रिश्ते पर नहीं, समाज पर भी पड़ता है। यह एक विकृति बनती जा रही है, जहां निजी दर्द सार्वजनिक मनोरंजन बन रहा है। और इसे प्रोत्साहन मिलता है व्यूज, लाइक्स और फॉलोवर्स की भूख से। एक जमाना था जब लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते थे – आज लोग लाइक और शेयर के लिए अपने रिश्ते खुद बर्बाद कर देते हैं। मीडिया से ज्यादा, मिडियाई मानसिकता दोषी है

यह केवल 'मीडिया ट्रायल' का मुद्दा नहीं है। असली समस्या उस मानसिकता की है जो कैमरा ऑन होते ही खुद को पीड़ित घोषित कर देती है और दर्शकों को जूरी बना देती है।

यह 'हाफ ट्रुथ पॉलिटिक्स' अब राजनीति तक सीमित नहीं रही – यह अब हमारे घरों में घुस चुकी है। लोग अपने गुस्से और दुख को शब्दों में नहीं, स्क्रिप्टेड कंटेंट में ढाल रहे हैं। और दर्शक भी, असल में मदद करने के बजाय, तमाशबीन बने रहते हैं – स्क्रीन के उस पार तालियाँ बजाते हुए।

रिश्ते सहारे से ज्यादा, स्क्रीन पर टिके हैं

इस डिजिटल युग में रिश्ते अब संवाद से नहीं, कंटेंट से चलने लगे हैं। पार्टनर से बात करने की जगह, लोग सोशल मीडिया पर 'इंडीरेक्ट' पोस्ट करते हैं। लड़ाई होती है, तो स्टोरी लगती है – ₹सब कुछ सहने की भी एक हद होती है₹। और फिर लाइक, कमेंट और शेयर की बाढ़ आती है, जो उस रिश्ते के फटे कपड़े में और कील ठोक देती है।क्या कोई रास्ता है इस डिजिटल ड्रामा से बाहर निकलने का? बिलकुल है। पर शुरूआत हमें ही करनी होगी। किसी भी झगड़े या विवाद को सार्वजनिक करने से पहले, अपने सबसे करीबी से निजी तौर पर बात करें। संवाद हर समस्या का पहला समाधान है। अगर मामला गंभीर है, तो परिवार, मित्र या थैरेपिस्ट की मदद लें। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियो बनाकर दुनिया से इंसाफ की उम्मीद न करें। अगर आप किसी का वीडियो या पोस्ट देख रहे हैं, तो एकतरफा निर्णय न लें। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और कभी-कभी सच्चाई दोनों के बीच कहीं होती है। हर रिश्ता अपने आप में एक दुनिया होता है। उसे सार्वजनिक चौराहे पर न उधेड़ें। एक दिन वही दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है।

आज जब हर व्यक्ति अपने हाथ में मीडिया लेकर घूम रहा है, तब सबसे बड़ा ज़िम्मेदार भी वही है। कैमरा ऑन करना आसान है, पर सच्चाई को ईमानदारी से दिखाना मुश्किल। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और भरोसे की बुनियाद संवाद से मजबूत होती है, तमाशे से नहीं। हर बार लाइव आकर रोना-धोना करने से सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं बचते। और जब दूसरा पक्ष सामने आता है, तो फिर न सिर्फ.रिश्ता, बल्कि भरोसा भी मरता है – उस इंसान का भी और उस समाज का भी, जो बस 'लाइव' देखकर न्याय करने को तैयार बैठा था। इसलिए अगली बार जब कोई रोता हुआ वीडियो सामने आए – जरा रुकिए। सवाल पूछिए, दोनों पक्षों को सुनिए। क्योंकि असल इंसाफ वही है जो तटस्थ हो, और इंसाफ के बिना कोई भी तमाशा बस एक और रिश्ते की मौत होती है – डिजिटल स्टेज पर।



– डॉ.सत्यवान सौरभ

भाजपा दक्षिण में अपनी जड़ों को मजबूत करने को तत्पर

सर्वविदित है कि भाजपा के लिए तमिलनाडु केवल राजनीतिक संघर्ष का मैदान नहीं है, वैचारिक लड़ाई भी लड़ी जानी है। स्टालिन सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विवादित करने और त्रिभाषा सिद्धांत को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में प्रचारित करने से केंद्र आहत है, इसीलिये भाजपा अपने राजनीतिक सिद्धांतों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को गंभीर चुनौती दे रहे इन नेताओं और दलों को वैचारिक धरातल पर परास्त करने का रास्ता भी खोज रही है।



आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, लेकिन अब भाजपा दक्षिण में अपनी जड़ों को न केवल मजबूत करना चाहती है बल्कि दक्षिण के राज्यों में सत्ता पर काबिज भी होना चाहती है। तमिलनाडु में अगले वर्ष अप्रैल-2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने 2026 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को अपनी महत्वपूर्ण चैन्नई यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अहम राजनीतिक गठबंधन का ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में एनडीए एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गठबंधन का चेहरा होंगे। तमिलनाडु की भाजपा में भी एक बड़ा बदलाव सामने आया है और भाजपा की तमिलनाडु इकाई की कमान नैनार नागेंद्रन को मिल गई है। भाजपा की राजनीतिक यात्रा में 2026 का तमिलनाडु चुनाव मील का पत्थर साबित होगा, वर्षों की प्यास को बुझायेगा, कमल खिलायेगा।

यह बात तो जगजाहिर है कि दक्षिण में हिन्दू मन्दिरों एवं संस्कृति का वर्चस्व होते हुए भी भाजपा अब तक अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई है, जबकि केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु हो, भाजपा अपनी जड़ों को सुदृढ़ करने की जद्दोजहद करती रही है। भाजपा के प्रयास दक्षिण में बेअसर ही रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है, समय-समय पर उसके प्रयास रंग लाते रहे हैं। दक्षिण के चार में से तीन राज्यों में भाजपा अपना प्रभाव और प्रभुत्व दिखा चुकी है। कर्नाटक में कई बार भाजपा सत्ता आसीन हो चुकी है, आंध्र प्रदेश में इस समय सत्ता की भागीदार है, तेलंगाना में भी भाजपा मजबूत पकड़ बना चुकी है, केवल तमिलनाडु ही है जहां भाजपा कई दशकों से उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पायी है। मोदी के प्रभाव और भाजपा के विशाल संसाधनों के बावजूद तमिलनाडू जीतना उसके लिए मुश्किल रहा है। पिछले 78 सालों में यहां कभी भी भाजपा-संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा या हिंदुत्व के उनके संस्करण को स्वीकार नहीं किया है। यह सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति एवं तैयारियों एवं मोदी-शाह के संकल्पों एवं इरादों में दम है, तमिलनाडु में आमूल-चूल परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक रणनीति में किये गये बदलाव एवं रणनीतियां एक बड़ा मोड़ है, एक नया उजाला है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह का यह भरोसा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा और राज्य में सरकार बनाएगा, कोरी हवा में उछाली गयी बात नहीं है। एआईडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन 1998 से बनते-बिगड़ते रहे हैं। 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने और फिर 13 महीने बाद उसे गिराने का श्रेय भी एआईडीएमके को जाता है। जे. जयललिता का जब तक जीवनकाल रहा तब तक भाजपा नेतृत्व के साथ एआईडीएमके की नजदीकियां बनी रही। जब 1999 में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो करुणानिधि ने डीएमके को भाजपा के साथ जोड़ लिया और 2004 तक सत्ता का सुख लेते रहे। 2004 के आम चुनाव में फिर से एआईडीएमके भाजपा के साथ आई लेकिन तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें नहीं जीत सकी। लेकिन मोदी-शाह की नजरें हमेशा इस राज्य पर लगी रही। क्योंकि सामरिक रूप से तमिलनाडु एक संवेदनशील राज्य है, श्रीलंका के साथ उसका सीधा जुड़ाव है। चीन श्रीलंका के माध्यम से भारत में पैठ बनाना चाहता है, ऐसे में तमिलनाडु में केंद्र की आंख बंद कर विरोध करने वाली पार्टी का सत्तासीन रहना देश हित के लिए गंभीर सवाल पैदा करता है, अनेक संकटों का कारण बन सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपने तीसरे कार्यकाल की बड़ी चुनौतियों में बंगाल, तमिलनाडु, केरल को जीतना है। वैसे इन राज्यों में भाजपा की जीत एक करिश्मा ही होगा, लेकिन मोदी-शाह ऐसे आश्चर्यकारी करिश्में घटित करते रहे हैं। सर्वविदित है कि भाजपा के लिए तमिलनाडु केवल राजनीतिक संघर्ष का मैदान नहीं है, वैचारिक लड़ाई भी लड़ी जानी है। स्टालिन सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विवादित करने और त्रिभाषा सिद्धांत को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में प्रचारित करने से केंद्र आहत है, इसीलिये भाजपा अपने राजनीतिक सिद्धांतों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को गंभीर चुनौती दे रहे इन नेताओं और दलों को वैचारिक धरातल पर परास्त करने का रास्ता भी खोज रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्राओं एवं अन्य चचाओं में यह बताते रहे हैं कि पूरे तमिलनाडु की जनता एवं राज्य उनके दिल में हैं, वे उसके कल्याण एवं विकास के लिये तत्पर है। तमिल लोगों के दिलों को जीतने का काम अकेले भाजपा के द्वारा संभव नहीं है, इसीलिये एआईडीएमके की बैशाखियां उसके लिये जरूरी है।

भाजपा के राजनीतिक समीकरणों की सार्थक निष्पत्ति का एक हिस्सा है एआईडीएमके और भाजपा के ताजा गठबंधन की घोषणा। इस गठबंधन को सहज बनाने और पार्टी के अनुरूप इसका स्वरूप देने का श्रेय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, क्योंकि इस बार यह काम उतना आसान नहीं था। शाह एक कद्दावर नेता होने के साथ राजनीतिक गणित को समझने में माहिर है। अमित शाह जमीनी हकीकत से हमेशा वाकिफ रहते हैं। उनके पास तमिलनाडु को लेकर साफ तस्वीरें हैं, सुस्पष्ट एजेंडा है। वह एआईडीएमके के साथ अभी से उदार एवं लचीली सोच से चलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य पता है। डीएमके एवं स्टालिन का अहंकार ही उनका मुख्य हथियार होगा। विकास के लिये सत्ता परिवर्तन जनता के लिए यदि जरूरी है तो उसे हासिल करने का तरीका भला अमित शाह से ज्यादा कौन जानता होगा।

तमिल में भाजपा के पांव जमते हुए दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा की सोच में बदलाव आना, तमिलों की बारीकियों एवं भावनाओं को समझते हुए राजनीतिक दांव चलना। भाजपा के पास द्रविड़ समाज को आकार देने का भले ही संस्थागत इतिहास नहीं है, लेकिन राज्य के विकास में उसने गहरे.संसाधन लगाये हैं। वह एक नया वोट-आधार तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने काशी और तमिलनाडु के बीच विभेद को खत्म करने की कोशिश की। धार्मिक राजत्व का तमिल प्रतीक सेंगोल संसद में स्थापित किया गया। ऐसे अनेक सकारात्मक प्रयास भाजपा के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। त्रिभाषा फामूर्ला भी तमिल लोगों को भाषा के नाम पर जोड़े रखने का एक उपक्रम है। मोदी और शाह दोनों ने तमिल भाषा के प्रति पार्टी के सम्मान को परिभाषित किया। पिछले दशक का एक बड़ा राष्ट्रीय घटनाक्रम यह रहा है कि भाजपा ने चुपचाप अपने नारे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान में सुधार किया है। अब वे हिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं। इन सबके चलते यदि तमिल के जातीय-मतदाता भाजपा को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार करेंगे, तब यह भारतीय सेकुलर राजनीति की एक क्रांतिकारी घटना होगी। शाह की रणनीति सही दिशा में काम कर रही है। बावजूद यह डगर चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि डीएमके दुबारा सत्ता में आने के लिए जो नुस्खा तैयार कर रही है उसमें तमिल स्वाभिमान और भाषा विवाद का घोल मिलाया जा रहा है। स्टालिन और उनका पूरा परिवार इस समय घोर भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों में लिप्त है लेकिन उन्होंने हिंदी विरोध, दक्षिण के साथ केन्द्र का कथित सौतेला व्यवहार और मनमाने परिसीमन जैसे मुद्दों को आगामी चुनाव का एजेंडा बनाया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु यात्रा में जानबूझ कर मुख्यमंत्री स्टालिन गायब हो गए, जबकि यह एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि प्रधानमंत्री प्रांत में आये तो मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें। लेकिन ऐसा न करके स्टालिन ने यह जताया कि डीएमके भाजपा विरोध के साथ-साथ केंद्र से टकराव की राजनीति पर है।

नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर

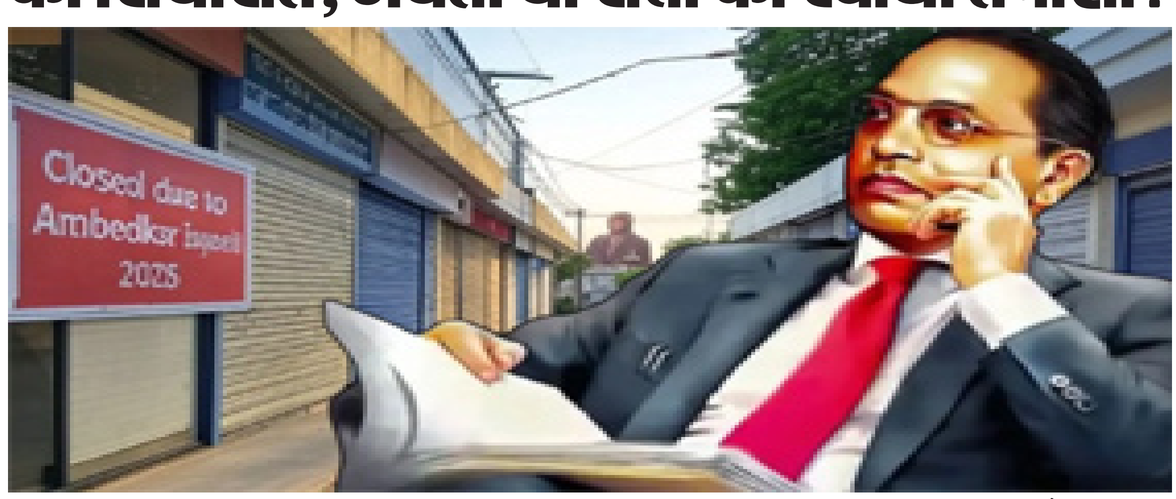
पिछले छः दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आई और चली गई मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। नक्सलवाद प्रभावित जिलों में उनकी हुकूमत चलती थी। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था जिसे लोग मानने को मजबूर थे। मगर अब परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दिया है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई है। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं। अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एस-सीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था। सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं।

देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

बाबा साहेब की विरासत पर सत्ता की सियासत, जयंती या सत्ता का स्वार्थी तमाशा?

बाबा साहब के विचारों—जैसे सामाजिक न्याय, जातिवाद का उन्मूलन, दलित-पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी, और संविधान की गरिमा की रक्षा—को आज के राजनेता पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। राजनीतिक दल केवल वोट बैंक के लिए अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, जबकि वे उनके विचारों से कोसों दूर हैं। जिन मुद्दों के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया—जैसे आरक्षण की सामाजिक भूमिका, जातिगत जनगणना, आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व—उन्हें आज भी दरकिनार किया जा रहा है। संसद और विधानसभाओं में पूंजीपतियों, सेलेब्रिटीज को भेजा जा रहा है, जबकि वंचित वर्ग हाशिए पर है। क्या बाबा साहब की आत्मा तब तक संतुष्ट हो सकती है जब तक उनके सपनों का भारत साकार न हो? यदि सच में अंबेडकर को श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके विचारों को व्यवहार में लाना होगा—वरना यह सब केवल एक दिखावा और ढोंग ही रह जाएगा।



देश भर में आज बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों की घंटियों की तरह मंचों पर माइक बज रहे हैं, फूलों की माला और भावुक भाषणों की बाढ़ है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लगातार मन को कुरेदता है – क्या यह श्रद्धांजलि है या सत्ता की साधना?

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे अछूत समझा जाता था। सामाजिक बहिष्कार और अपमान के बीच उन्होंने शिक्षा हासिल की और कोलंबिया विश्वविद्यालय व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह उपलब्धि अपने आप में उस समय के भारत में एक क्रांति थी। बाबा साहेब ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया – एक ऐसा धर्म जो समता, करुणा और ज्ञान की राह दिखाता है। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं – बशर्ते उन्हें ज़िंदा रखा जाए।

आज जब हम संसद और विधानसभाओं की तरफ नजर डालते हैं, तो पाते हैं कि वहां बड़े पैमाने पर पूंजीपति, अभिनेता, खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन जो बहुजन समाज सत्ता की सीढ़ी बनता है, उसे नीचे ही रहने दिया जाता है। जातिगत जनगणना से बचने वाली सरकारें, सामाजिक न्याय को स्थायी नीति में बदलने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि समाज में गहराई से असमानता बनी हुई है।

बाबा साहब की जयंती पर करोड़ों रुपये खर्च कर देना, बड़ी रैलियां और पोस्टर लगवा देना, उनकी मूर्तियों को फूलों से ढक देना – क्या यही श्रद्धा है? क्या ये वही लोग नहीं हैं जो बाबा साहब की किताबें कभी पढ़ते तक नहीं? क्या ये वही सियासी दल नहीं हैं जिनकी नीतियां प्रत्यक्ष रूप से संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाती हैं?

यह ढोंग तभी रुकेगा जब हाथी के दांत खाने और दिखाने के एक कर दिए जाएं। जब कथनी और करनी में फर्क मिटेगा। और जब शासन सत्ता में सभी को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी – तभी हम कह सकेंगे कि हमने बाबा साहब को सही मायनों में श्रद्धांजलि दी है।

जिस बाबा साहेब ने भारत के सबसे दबे-कुचले, हाशिए पर पड़े वर्गों को आवाज दी, संविधान में उनके अधिकार सुनिश्चित किए, उन्हीं के नाम पर आज वही लोग जयंती मना रहे हैं जिन्होंने उनके विचारों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा था: ₹मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं – यह मेरे वश में है।₹ इस ऐतिहासिक उद्घोषणा को समझने के बजाय, राजनेताओं ने उन्हें मूर्तियों तक सीमित कर दिया। संविधान, जिसे उन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों की रक्षा के लिए लिखा था, उसे आज बेतरतीब तरीके से तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।

बड़े दुख की बात है कि जिन दलों का जन्म ही दलितों और पिछड़ों के हक के लिए हुआ था, वे आज या तो सत्ता के लालच में चुप हैं या डर के मारे मौनव्रत धारण किए हुए हैं। बसपा जैसे दल बाबा साहेब का नाम लेकर सत्ता में आए, लेकिन आज उनके सिद्धांतों की रक्षा में सबसे पीछे हैं। सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह गया है बाबा साहेब का नाम। आरक्षित सीटों से विधायक-सांसद बनने वाले लोग अपने-अपने दलों की गुलामी में मग्न हैं। वे दलित हितों पर हो रहे प्रहारों को मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं। ऐसे में एक साधारण नागरिक के तौर पर मैं, विनेश ठाकुर, इन सत्ता-भोगी प्रतिनिधियों की कठोर निंदा करता हूँ।

आज जो लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश ने उनके विचारों पर एक कदम भी चलने का साहस नहीं दिखाया। जातिगत जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी, शिक्षा और रोजगार में बराबरी जैसे मुद्दे आज भी लंबित हैं। इसके बजाय गरीबों को फ्री राशन देकर खुश करने की नीति अपनाई जा रही है – स्थायी रोजगार और गरिमा भरे जीवन की जगह भीख सरीखा जीवन दिया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में बड़े-बड़े उद्योगपति, अभिनेता और खिलाड़ी पहुँचते हैं, लेकिन जिनके वोटों से सरकारें बनती हैं – दलित, आदिवासी, ओबीसी – वे आज भी हाशिए पर हैं। बाबा साहेब की असली विरासत की हत्या हो चुकी है और अब उनकी जयंती सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट बन गई है।

उनकी जीवनी सबको मालूम है – 14 अप्रैल 1891, महू (मध्यप्रदेश) में जन्म, अछूत मानी जाने वाली महार जाति से संबंध, बचपन में भेदभाव का शिकार, लेकिन अद्वितीय प्रतिभा से दुनिया को चौंका देने वाला व्यक्तित्व। उन्होंने पूरी दुनिया से ज्ञान अर्जित कर भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक विद्रोह किया। वे जीवन भर छुआछूत, जातिवाद, असमानता और राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ संघर्ष करते रहे। लेकिन आज, उनके नाम पर सिर्फ भीड़ जुटाई जा रही है, विचार नहीं। राजनीतिक दलों से मेरा सीधा सवाल है – क्या आपने सामाजिक न्याय के लिए कोई ठोस कदम उठाया? जवाब स्पष्ट है: शून्य।

यदि वास्तव में आप बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो एक वर्ष के लिए धार्मिक आयोजनों, दिखावटी अभियानों और मूर्ति अनावरणों का बजट काटिए। उस पैसे से सभी जातियों के लिए आर्थिक आधार पर न्याय की व्यवस्था कीजिए। सत्ता में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए। 50% कमीशनखोरी बंद करिए, निजीकरण की लहर पर विराम लगाइए।

अगर आप यह कर सकें, तो यकीन मानिए – बाबा साहेब की आत्मा कहेगी, ₹अब तुमने मेरे विचारों को सिर्फ याद नहीं किया, बल्कि जिया है।₹ वरना, हाथी के दिखाने और खाने के दांतों में फर्क बना रहेगा – और यह फर्क ही एक दिन लोकतंत्र को निगल जाएगा।



-प्रियंका सौरभ



तल्खी सूरज की, लोग हुए बेहाल

बांदा। चार दिन पहले बूंदाबांदी और बदली से तापमान में कुछ कमी आई थी, लेकिन सूर्य की तल्खी फिर लोगों को बेहाल कर रही है। गुरुवार को दोपहर में 36 किलोमीटर की गति से तेज गर्म हवाएं चलीं। घरों से निकले राहगीर बेहाल नजर आए। स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी के बाद छात्र-छात्राओं की घर पहुंचने में हालत खराब हो गई। मौसम विभाग दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर बदली और बूंदाबांदी के आसार बता रहा है।

केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गत गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री और न्यूनतम तापमान दो डिग्री ज्यादा है। दिन में हवाओं का रुख बदला रहा। सुबह पुरवा हवाओं ने गर्मी से कुछ सुकून पहुंचाया। दोपहर में पश्चिम से 36 किलोमीटर की गति से तेज गर्म हवाएं चलीं। इस कारण अब दिन व रात दोनों गर्म हो रहे हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ.दिनेश शाहा का कहना है कि दो दिन बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है। इसके चलते बुंदेलखंड में मौसम में बदलाव होगा। तेज हवाएं चलने के साथ ओलों के साथ बारिश के आसार हैं। उधर, गुरुवार को सुबह 11 बजे के बाद ही सूर्य की तपिश असहनीय हो गई। स्कूलों में 12 बजे दोपहर छुट्टी हुई तो बच्चों की तेज धूप में घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह किसी तरह सिर ढककर घर पहुंचे।

इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड, स्टेशन, संकटमोचन मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी दोपहर में तेज धूप व गर्मी के चलते लोगों की संख्या बेहद कम रही। गर्मी का असर बाजार में भी देखा गया। दोपहर में ग्राहक आने से बचते हैं। सुबह-शाम ही मात्र ग्राहकों के दर्शन दुकानों व सड़कों पर होते हैं।

मंजूषा 2025 प्रदर्शनी का हुआ आयोजन

सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में बुधवार को गृह विज्ञान विभाग द्वारा रचनात्मक प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु मंजूषा 2025 नामक एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विभाग की छात्राओं ने हस्तनिर्मित एवं पुनः उपयोग की गई सामग्रियों से तैयार की गई वस्तुओं को प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

प्रदर्शनी में प्रस्तुत प्रमुख उत्पादों विशेष रूप से अपशिष्ट सामग्री से निर्मित इयररिंग्स, कीचेन, डोर तोरण, फोटो फ्रेम, शोपीस, डोर हैंगिंग्स, कोस्टर्स, फूल, फूलदान, बंधेज कार्य वाले दुपट्टे, हाथ से सिले रुमाल, तथा अन्य सजावटी एवं उपयोगी वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। साथ ही, छात्राओं द्वारा तैयार किए गए खाद्य उत्पाद जैसे अचार, सिरका, नमकीन, केले के चिप्स, माउथ फ्रेशनर, मूंगफली के गिफ्ट हैम्पर्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

इन वस्तुओं को गृह विज्ञान की छात्राओं ने अपनी कक्षा के अभ्यास कार्यों के अंतर्गत पूर्णतः स्वयं तैयार किया गया था। छात्राओं द्वारा लगाए गए खाने के स्टाल गुलाब जामुन, पनकम आदि ने भी खूब तारीफ बटोरी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विवि की कुलपति प्रो. कविता शाह ने छात्राओं की प्रशंसा करते हुए कहा मंजूषा 2025 केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि हमारी छात्राओं की प्रतिभा, नवाचार और आत्मनिर्भर सोच का प्रतिबिंब है। यह प्रयास उन्हें शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन के लिए भी तैयार करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम से विद्यार्थियों के अंदर रचनात्मक दृष्टि एवं नवाचार के प्रति आकर्षक तो बढ़ता ही है साथ में अन्य विद्यार्थी भी इससे प्रेरित होते हैं और वर्तमान परिवेश में विद्यार्थियों के अंदर रचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि विकसित करना शिक्षण कौशल का महत्वपूर्ण आयाम है। कार्यक्रम की संयोजक एवं गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी डॉ रक्षा ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राओं ने न केवल अपने कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सीमित संसाधनों द्वारा जीवन मे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से मंजूषा नवाचार का एक उत्सव के रूप में परिगणित किया जा सकता है। रिसोर्स पर विश्वविद्यालय के वाणिज्य कला एवं विज्ञान के डीन, मुख्य नियन्ता, विभागाध्यक्ष शिक्षक छात्राएं उपस्थित रहे।

सामाजिक समानता की प्रतिमूर्ति थे डॉ. आंबेडकर



कुशीनगर (रहसू बाजार)। रहसूजनोबी पट्टी के पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि फाजिलनगर विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने डॉ. अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलित किया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर सामाजिक समानता, न्याय और मानव अधिकारों के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं सहित अन्य वंचित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कार्यक्रम को सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी, प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रधान ठाकुर अरबिंद सिंह, बीएसपी नेता जयश्रीप्रसाद, मनीष तिवारी, रामदयाल उर्फ गुड्डू प्रधान ने संबोधित किया।

शिक्षिका ज्योति विश्वकर्मा को मिला पारस रत्न अवार्ड

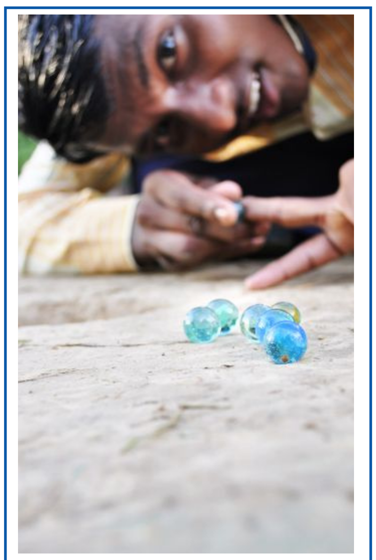


बांदा। उच्च प्राथमिक विद्यालय जारी में तैनात शिक्षिका ज्योति विश्वकर्मा को पारस रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मिला है।

बड़ोखर खुर्द ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय जारी भाग-एक में तैनात सहायक अध्यापिका ज्योति विश्वकर्मा श्रेष्ठ नवाचारों व शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। पारस एजुकेशन संस्थान की ओर से बरेली के खुशलोक अस्पताल सभागार में 13 अप्रैल को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश से 51 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथि बरेली लोकसभा सांसद छत्रपाल गंगवार और महापौर बरेली उमेश गौतम एवं पर्यावरण राज्य मंत्री से अरुण कुमार ने शिक्षिका ज्योति विश्वकर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृतिचिह्न, अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया। पूर्व में भी शिक्षिका ज्योति विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं।

बसपा नेताओं ने किया बाबा साहब के योगदान पर विमर्श

बस्ती। भारतीय संविधान के निमार्ता और समाज के दलितों, उपेक्षित वर्ग को राह दिखाने वाले बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर को उनकी 135वीं जयंती पर याद किया गया। नगर पंचायत, नगर पालिका एवं न्याय पंचायत स्तर पर बसपा नेताओं, कार्यकताओं ने बाबा साहब को नमन किया। बड़ेवन के निकट स्थित एक होटल के सभागार में जिलाध्यक्ष अनिल गौतम के संयोजन में गोष्ठी आयोजित की गई। बसपा नेताओं ने बाबा साहब के योगदान पर विमर्श किया। मुख्य मंडल प्रभारी धर्मदेव प्रियदर्शी ने कहा कि हमें बाबा साहब के संकल्पों को साकार करने के लिए एक जुट होना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी संजय धूसिया, राजेंद्र गौतम आदि ने बाबा साहब के योगदान पर प्रकाश डाला।



मेडिकल कॉलेज में एक्सरे के लिए मरीजों ने किया हंगामा

पडरौना (कुशीनगर)। मौसम में बदलाव के कारण मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। मंगलवार को बिना एक्सरे कराए 100 से अधिक मरीजों को लौटा दिया गया। नाराज तीमारदारों और मरीजों ने हंगामा किया तो कक्ष छोड़कर टेक्निशियन हट गए। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अपनी पर्ची लेकर मरीज वापस चले गए। तीन दिन से मरीजों को एक्सरे कराने के लिए दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में आने वाले खासी, सांस फूलने और हड्‌टी फ्रैक्चर वाले मरीजों को एक्सरे के लिए डॉक्टर लिख रहे हैं। मंगलवार को 200 मरीजों ने पर्ची लगाया था, इसमें कुछ मरीज एक दिन पहले के थे। करीब 70 मरीजों का एक्सरे हुआ, बाकी मरीजों को पर्ची देकर दूसरे दिन आने की बात कह टेक्निशियन लौटाने लगे। मरीजों ने विरोध किया तो कहासुनी भी टेक्निशियन से हुई। नाराज मरीज हंगामा करने लगे तो एक्सरे कक्ष में बैठे स्वास्थ्यकर्मी वहां से



भीड़ होने के कारण कुछ लोग हंगामा किए थे, जिनका जरूरी था उसका एक्सरे हुआ। इसमे सुधार के लिए एक्सरे टेक्निशियनों को निर्देश दिया गया है।
- प्राचार्य डॉ. आरके शाही

उठकर चले गए। करीब एक घंटे तक मरीज इंतजार किए लेकिन एक्सरे नहीं हुआ। बाद में एक टेक्निशियन आया और सभी मरीजों का जमा किया गया पर्ची वापस कर दूसरे दिन आने को कहा।

मरीजों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर मनमानी किया जा रहा है। एक्सरे के लिए सोमवार को भी 100 से अधिक मरीजों को लौटा दिया गया। एक्सरे टेक्निशियन का कहना है कि एक दिन में 70 से अधिक एक्सरे नहीं किया जा सकता। इसके लिए दूसरे दिन बुलाया जा रहा है। रमावती, प्रभावती, सुंदरम, हीरा, रूपक ने बताया कि दस किमी दूरी तक कर इलाज के लिए आए थे, एक घंटे कतार में लगने के बाद डॉक्टर ने तो देखा, लेकिन तीन घंटे इंतजार के बाद भी एक्सरे नहीं हुआ।

दूसरी ओर वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बुखार के तीन से पांच फीसदी मरीजों में महक और स्वाद न आने की भी समस्या सामने आ रही है। हालांकि न तो किसी मरीज का ऑक्सीजन स्तर कम हो रहा है और न ही बहुत गंभीर स्थिति हो रही है। ऐसे में वायरल का कोई नया स्ट्रेन हो सकता है। दवा का नियमित सेवन करने पर मरीजों को एक हफ्ते में स्वाद और महक लौट आती है।

बाघनगर, कम्हरिया व टेमारहमत ग्रामसभा में बनेंगे अंत्येष्टि स्थल

संत कबीर नगर। सेमरियावां ब्लॉक के तीन ग्राम पंचायतों में नदियों के किनारे अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। इसके लिए शासन से धन अवमुक्त हो गया है। पंचायत राज विभाग निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की कवायद में जुट गया है। सेमरियावां ब्लॉक में 113 ग्राम पंचायत हैं। जिसमें से बाघनगर, कम्हरिया और टेमारहमत ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए स्वीकृत प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार को लेकर होने वाली परेशानियों को देखते हुए शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन ग्राम पंचायतों में नदियों के किनारे अंत्येष्टि स्थल बनाने का निर्णय लिया है। शासन के निर्देश पर जिला पंचायत राज विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था। जिसके बाद शासन की तरफ से अंत्येष्टिस्थल के निर्माण के लिए धनराशि संबंधित ग्राम पंचायतों के खाते में भेजी गई है। प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल पर 24.11 लाख रुप की धनराशि खर्च होगी।

▸ खंडवा के काले परिवार को गौरैया संरक्षण के लिए कलेक्टर ने भेजा प्रशस्ति पत्र

घर की छत को बनाया गौरैयाओं का सुरक्षित आश्रय, पर्यावरण प्रेम की मिसाल बना मन गार्डन

खंडवा। प्रकृति से प्रेम जब समर्पण में बदलता है, तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता—वह पूरे समाज को प्रेरणा देने लगता है। खंडवा के दादाजी वार्ड निवासी मुकेश काले और उनके परिवार ने अपने घर की छत को मन गार्डन के रूप में विकसित किया है, जो आज गौरैयाओं और अन्य पक्षियों का सुरक्षित और आत्मीय आश्रय बन गया है।

इस प्रेरणादायक कार्य के लिए कलेक्टर खंडवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा 8 अप्रैल को काले परिवार के नाम प्रशस्ति पत्र भेजा गया, जिसे पटवारी श्री अशोक सिंह तंवर के माध्यम से उनके निवास स्थान पर प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुकेश काले की पत्नी पूर्णिमा काले, बहू विनीता काले तथा पुत्र अर्थव काले भी उपस्थित रहे।



कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने प्रशंसा में लिखाः

प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में आपके परिवार द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। यह समाज को नई दिशा देने वाला प्रेरणादायक प्रयास है। जिला प्रशासन सदैव इस प्रकार के प्रयासों के साथ खड़ा रहेगा।

मन गार्डन बना गौरैयाओं का घर

मुकेश काले ने लगभग दस वर्षों की मेहनत से अपनी छत को हरियाली, लकड़ी के छोटे घरों, दाना-पानी और छायादार स्थानों से सजाया है। अब यह स्थान न सिर्फ गौरैयाओं बल्कि अन्य पक्षियों के लिए भी एक स्वर्ग जैसा बन गया है। उनकी पत्नी पूर्णिमा काले, बहू विनीता काले, और बेटे आदित्य व अर्थव इस सेवा में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं।

पूर्णिमा काले कहती हैं, अब गौरैया हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हैं। उनकी चहचहाहट से दिन शुरू होता है और शाम को लौटती हैं, जैसे ये हमारे अपने घर की सदस्य हों।

पर्यावरण प्रेमः जीवनशैली में रचा-बसा संकल्प

जब स्त्रियाँ मायके जाती हैं, तो अक्सर कपड़े, उपहार या पसंदीदा वस्तुएँ साथ ले जाती हैं। लेकिन श्रीमती पूर्णिमा काले का मायके जाना एक अलग ही प्रेरणा देता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा है कि वे आज जब अपने मायके इंदौर गईं, तो साथ ले गईं पौधे, कलमें और हरियाली की सौगात। उनका मानना है कि जहाँ भी रहें, वहाँ हरियाली और प्रकृति की सुंदरता जरूर हो। यह सोच ही ह्यमन बगियाह्ल की आत्मा है, और यही भावना उन्हें हर स्थान को प्रकृति से जोड़ने की प्रेरणा देती है।

मित्र भी हुए प्रेरित

मुकेश काले के मित्र हेमंत मोराने बताते हैं कि मुकेश भाई ने यह साबित कर दिया कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनका यह कार्य न केवल पर्यावरण प्रेम की मिसाल है, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा भी है।

प्रकृति संरक्षण की ओर एक प्रेरक संदेश

काले परिवार की यह पहल आज पूरे खंडवा में चर्चा का विषय बन गई है। यह दिखाता है कि यदि संकल्प हो तो प्रकृति से जुड़ाव फिर से स्थापित किया जा सकता है। प्रकृति से जुड़ाव ही सच्चे समृद्ध जीवन की नींव है।

नशा मुक्ति अभियान के तहत शोभायात्रा, किया जागरूक

पडरौना (कुशीनगर)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से देश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों को बताकर लोगों को किसी भी तरह का नशा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। नशा मुक्ति अभियान में शामिल जागरूकता गाड़ी को डीएम विशाल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट से निकाली शोभा यात्रा रविंद्र नगर चौक से होते हुए छावनी, सुभाष चौक, तिलक चौक, जटहां रोड से होते हुए अंबे चौक पहुंची जहां नशा से होने वाले नुकसान की जानकारी देकर शोभा यात्रा का समापन हुआ।

सड़क खोदकर छोड़ने से उड़ रही धूल, राह चलना दूभर

वाल्टरगंज। डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क खोदकर छोड़ दी गई है। जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। वाहनों के आने-जाने से धू उड़ रही है। इससे राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। धूल का गुबार इतना घना हो जा रहा है कि वाहन चालकों को आगे दिखाई नहीं दे रहा है। वाहनों के लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। साइकिल और पैदल चलने वाले धूल-धुसरित हो जा रहे हैं। इस रोड से गुजरने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

डुमरियागंज मार्ग के चौड़ीकरण के लिए खोदाई की गई है।

रोड निर्माण के लिए बालू और मिट्टी गिराई जा रही है। इसके कारण धूल का गुबार उड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि अगर निमार्णाधीन सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता तो लोगों को आने-जाने में दिक्कत नहीं होती।

क्षेत्र के आनंद रजन, श्याम, राजेश राजभर, संजय राजभर, राम ललित, शहवाज खान, विजय, राम नेव-इस ने बताया कि सड़क पर धूल उड़ने के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चहिए।

टॉफी-बिस्कुट की दुकान की पुड़िया से स्कूल-अस्पताल में सुलग रही चिलम

गुरवलिया बाजार (कुशीनगर)। असम, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश से बिहार होते हुए पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में गांजा की खेप ले जाते समय जिले में भी इसकी डिलिवरी की जा रही है।गांजा असम, ओडिशा से बड़ी गाड़ियों से होते हुए जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्सल की तरह सफेदपोशों के पास पहुंच रहा है। फिर बंडल वाली यही गांजा गांव में खुली टॉफी-बिस्कुट वाली गुमटियों तक पहुंचाई जा रही है। जहां से गांव के युवा इसे पुड़िया के नाम से 20, 50 और 100 में खरीदकर गांव-गांव खंडहर बने प्राचीन विद्या के मंदिर, विद्यालयों और अस्पतालों में गांजा के चिलम में भरकर धुआं उड़ा रहे हैं। गांव-गांव में पीने वालों की संख्या बढ़ी है, जिससे तस्कर जोखिम उठाकर पार्सल की तरह गांजे की डिलीवरी कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को मऊ और इटावा के तस्करों के पास से कंटेनर सहित लाखों का गांजा बरामद किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गांजा की खेप असम से लेकर भले ही पश्चिमी यूपी तक ले जाते हैं, लेकिन इसकी पार्सल रूप में डिलीवरी हाईवे 27 और 28 पर पहले से ही डीलिंग के मुताबिक व्यक्ति को की जाती है। सूत्र बताते हैं कि कुशीनगर में सख्ती होने पर देवरिया से निकलने वाले कंटेनर से गोपालगंज में ही गांजा की खेप की डिलीवरी कर दी जाती है। गांव-गांव में युवाओं में गांजा की मांग अधिक होने पर से जिले और आसपास के तस्कर मोटर बाइक, लग्जरी कार आदि माध्यमों से बंडलों में रखकर फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं। अधिकांश टॉफी-बिस्कुट, किराना और पान सहित अन्य छोटी दुकानों से ही गांजा को युवा पुड़िया कोड शब्द देकर 10 से 50 रुपये देकर खरीदते हैं। सूत्र बताते हैं कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का बरवा राजापाकड़, खुदरा अहिरौली आदि इलाका पूर्व में गांजा तस्करों का हब रहा है। आज भी इन जगहों से छोटे दुकान तक गांजा सप्लाई होती है। थाना क्षेत्र के कसया-सेवरही मुख्य मार्ग पर तुर्कपट्टी बाजार में एक पान मसाला की गुमटी में गांजा की पुड़िया बेची जाती है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के विद्यालय, अस्पताल इन दिनों गांजा तस्करों का अड्डा बन गया है। यही नहीं गांजा की पुड़िया भी गांव के बाजारों में खुलेआम बेची जा रही है।

बदलते परिदृश्य में बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत : नसीम

सेमरियावां(संत कबीर नगर)। एआरसी पीजी कॉलेज मूड़ाडीहाबेग में मंगलवार को बदलता परिदृश्य और उसकी चुनौतियां विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान बंगलौर से आए एक्सपर्ट नसीम अहमद ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी क्षेत्रों में होने वाले निरंतर बदलाव को देखते हुए बच्चों को सही मार्ग दर्शन की जरूरत है। इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी बदलावों को समझना होगा। वैश्वीकरण, शहरीकरण और सांस्कृतिक विविधता के कारण समाज की संरचना बदल रही है। लोग अधिक जागरूक और जुड़े हुए हैं, लेकिन असमानता और सामाजिक तनाव भी बढ़ रहे हैं। नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। डिजिटल क्रांति, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स ने जीवन को तेज और जटिल बनाया है। तकनीकी प्रगति से कुछ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य पीछे छूट रहे हैं। इससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। बदलाव के साथ अपने आपको अपडेट रहने की जरूरत है। आईआईटी दिल्ली से आए मोवस्सिर सैयद अली ने कहा कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के माध्यम से लोगों को विभिन्न मुद्दों, विषयों और अवधारणाओं के बारे में जागरूक करना होगा। यह जागरूकता कार्यक्रम व्यक्तियों के ज्ञान और समझ को बढ़ाने, उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने और समस्याओं को हल करने की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा जागरूकता समाज के विकास और उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संचालन नेशनल इंटर कॉलेज मूड़ाडीहाबेग के प्रधानाचार्य मुजीबुल्लाह ने किया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादकः पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com